RNI No. 58061/93 ■ वर्ष - 21 ■ अंक - 329 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » सोमवार » 29-06-2026 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

2 बच्चे बोझ नहीं, बल्कि समृद्धि का स्रोत : मुख्यमंत्री नायडू

6 भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता का प्रश्न

7 सलमान खान को बांद्रा में छह मंजिला रिहायशी इमारत बनाने की मिली मंजूरी

फर्स्ट टेक

केरल में आईएमडी ने 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया

तिरुवनंतपुरम/भाषा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को समूचे केरल में बारिश होने के मद्देनजर 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार शाम केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) के माध्यम से जारी एक बयान में तिरुवनंतपुरम, कोलाम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के लिए रविवार को 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया। आईएमडी ने पहले छह जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था, जिसे बाद में केरल भर में बारिश तेज होने पर पांच और जिलों में बढ़ा दिया गया। रविवार को त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पुरी में भगवान जगन्नाथ की सालाना 'स्नान यात्रा' के लिए तैयारी पूरी

पुरी/भाषा। पवित्र शहर पुरी सोमवार को भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की 'स्नान यात्रा' (यानी स्नान उत्सव) के लिए तैयार है। राज्य सरकार ने रथयात्रा से पहले होने वाले इस कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 'स्नान यात्रा' का दिन भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी माना जाता है। देशभर से श्रद्धालु देवताओं की पारंपरिक 'पहांडी' (शोभा यात्रा) देखने के लिए इस तीर्थ शहर में पहुंचने लगे हैं, यह शोभा यात्रा सुबह पांच बजे से सात बजे के बीच निकाली जाएगी। देवताओं को 12वीं सदी के मंदिर परिसर में बने पवित्र स्थान 'स्नान मंडप' में लाया जाएगा, जहां पुजारी सभी लोगों के सामने प्रतिमाओं पर 108 घड़े का पानी डालेंगे।

पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा गया

मेंढर/जम्मू/भाषा। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रविवार को सेना के जवानों ने 31 वर्षीय एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा । अधिकारियों ने बताया कि इस महीने जिले में इस तरह की यह तीसरी घटना है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के निवासी रईस खान को नियंत्रण रेखा पार कर इस तरफ आने के तुरंत बाद बालाकोट सेक्टर से हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए घुसपैठिए के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पार से उसके इस तरफ आने के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है।

29-06-2026 सूर्यास्त 6:49 बजे | 30-06-2026 सूर्योदय 5:57 बजे

BSE	NSE
77,100.47 (+109.25)	24,056.00 (+34.35)

सोना	चांदी
14,698 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	229,146 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

दण्ड महात्म्य

पद की मर्यादाएं रखना,
नैतिक जिम्मेदारी है।
न्याय और न्यायालय ने भी,
यही बात स्वीकारी है।
दण्ड सचेतक है गलती का,
इसकी गरिमा न्यारी है।
इज्जतदारों के ऊपर तो,
इक रुपया भी भारी है।।

"भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को 'अवसरों का महासागर' बनाना है"

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

विक्टोरिया (सेशेल्स) /भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है, जहां समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी का आधार देशों का आकार नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और विश्वास हो। सेशेल्स की तीन-दिवसीय यात्रा पर आए मोदी ने यह भी कहा कि भारत और द्वीपों से बने इस देश की रक्षा और सुरक्षा एक-दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है।

सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''हमारा उद्देश्य हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना है।''

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

मोदी ने कहा, ''हम मानते हैं कि हिंद महासागर हमारा साझा घर है। इसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हमारी साझा जिम्मेदारी है।'' उन्होंने कहा कि यह भारत के 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति) विजन का मुख्य आधार है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक अहमियत पर ज़ोर देते हुए मोदी ने कहा, ''हमारा मानना है कि भारत और सेशेल्स की रक्षा और सुरक्षा एक-दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मज़बूत तथा भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार बनाने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम दोनों देशों के उद्योगों के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और सेशेल्स के बीच संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाएगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में अपने सफल अनुभव को सेशेल्स के साथ साझा करेगा।

रक्षा, डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य समेत 19 समझौतों की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता के बाद भारत और सेशेल्स ने रविवार को 19 महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की, जिससे रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। ये समझौते हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय देश सेशेल्स के साथ सुरक्षा, संपर्क, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बाद में यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1,250 करोड़ रुपये की ऋण सहायता सेशेल्स में प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में मदद करेगी।

टीकाकरण

रविवार को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मियों ने पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। अभियान का उद्देश्य बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय मंत्री शाह ने शुरू की 'पीएम-फैमिली केयर ट्रैकर' प्रायोगिक परियोजना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गांधीनगर/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां 'पीएम-फैमिली केयर ट्रैकर' (पीएम-एफसीटी) की प्रायोगिक परियोजना शुरू की, और कहा कि यह एकीकृत डिजिटल मंच यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल मंच यह सुनिश्चित करेगा कि गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को लगातार निगरानी और समय पर मदद के जरिए सरकार की सभी जरूरी सुविधाएं मिलें।

इस मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए, गांधीनगर के लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के कल्याणकारी मॉडल का अगला कदम है। उन्होंने दावा किया कि इस मॉडल ने 2014 के बाद से सेवा वितरण में बदलाव किया है और यह सुनिश्चित किया है कि लाभ सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंचे।

शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 70 करोड़ गरीब लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें घर, बिजली, शौचालय, नल से जल, एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त अनाज, पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'पीएम-फैमिली केयर ट्रैकर' इन कल्याणकारी उपायों को और आगे बढ़ाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक कमियों के कारण कोई भी पात्र बच्चा या मां सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

नड्डा नए सिरे से लागू करेंगे 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान'

नई दिल्ली/भाषा। भारत में एनीमिया (रक्त की कमी) से निपटने के प्रयासों को गति देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा सोमवार को यहां होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (सीसीएचएफडब्ल्यू) की 16वीं बैठक में 'एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान' के क्रियान्वन के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में बताया इन दिशा-निर्देशों के तहत मौजूदा रणनीति के ढांचे में विस्तार किया जाएगा। बयान में बताया गया कि इसमें सातवां लाभार्थी समूह, सातवां उपाय और सातवां संस्थागत तंत्र शामिल किया जाएगा। बयान के मुताबिक, जीवन के प्रारंभिक चरण से ही एनीमिया की समस्या के समाधान के महत्व को देखते हुए, जन्म के समय कम भार (एलबीडब्ल्यू) वाले शिशुओं (0-6 महीने) को सातवें लाभार्थी समूह के रूप में शामिल किया जाएगा।

द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने संकेत दिया

'टीवीके सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/भाषा। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने रविवार को संकेत दिया कि तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार उन दलों के समर्थन से चल रही है जो हाल तक उनके नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थे।

द्रमुक प्रमुख के बयान का परोक्ष रूप से यह अर्थ था कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली यह ''अल्पमत'' सरकार अगले तीन से छह महीनों के भीतर गिर सकती है।

चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान, जहां अन्य दलों के कार्यकर्ता द्रमुक में शामिल हुए, स्टालिन ने दावा किया कि सत्तारूढ़ टीवीके के पास स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने के लिए जनमत का पूर्ण अभाव है, क्योंकि उसने आवश्यक 118 के बहुमत के आंकड़े के मुकाबले केवल 108 सीट हासिल की हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, ''आइए हम वास्तविकता को देखें। वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने अपने दम पर एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं किया था।''

उन्होंने दावा किया, ''जनता ने वास्तव में द्रमुक को सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। यह केवल कुछ राजनीतिक दलों के रणनीतिक गठबंधन और समर्थन के कारण है जो हाल तक हमारे प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा थे कि यह टीवीके रूपी वाहन किसी तरह आगे बढ़ पा रहा है।''

तमिलनाडु की जनता अब पिछली शासन-व्यवस्था की तलाश कर रही है : उदयनिधि

चेन्नई/भाषा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के लोग अब उस शासन-व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं जो कभी उनके पास हुआ करती थी। विजय ने 23 जुलाई को राज्य विधानसभा में अपने समापन भाषण में उदयनिधि का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह अपने 'अप्पा' (द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन) को ढूंढ़ रहे हैं, जो सदन में नहीं मिल सकते थे। यह टिप्पणी विधानसभा चुनाव में स्टालिन की हार के संदर्भ में की गई थी। पुडुकोट्टई में एक शादी समारोह में उदयनिधि ने कहा, ''तमिलनाडु में कभी एक शासन-व्यवस्था हुआ करती थी। आज राज्य के लोग ढूंढ़ रहे हैं कि वह शासन-व्यवस्था कहां चली गई है।'' उन्होंने सत्ताधारी टीवीके सरकार पर आरोप लगाया कि वह बार-बार द्रमुक को छापेमारी के जरिए निशाना बनाती है, जबकि 'भ्रष्ट ताकतों' का स्वागत करती है। उनका आरोप था कि ये ताकतें पार्टी में शामिल होने के बाद 'पवित्र ताकतें' बन जाती हैं।

सीईआरटी-आईएन ने

व्हाट्सऐप वेब के जरिए फैल रहे मैलवेयर को लेकर किया आगाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कैस्परस्की और सिक्योरलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरा पैदा करने वाले लोग हैक किए गए व्हाट्सऐप अकाउंट का इस्तेमाल करके सीधे पीड़ितों को खतरनाक फाइल भेजते हैं। इससे मैसेज असली लगते हैं और सफल हमले की आशंका काफी बढ़ जाती है।

नई दिल्ली/भाषा। व्हाट्सऐप वेब और डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर के जरिए बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के उपकरणों तक अनधिकृत पहुंच बनाने तथा संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की जा रही हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) ने यह जानकारी दी।

सीईआरटी-आईएन ने व्हाट्सऐप वेब और डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं को किसी भी फाइल को लेकर सावधान रहने की चेतावनी दी है, भले ही वे किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य की तरफ से ही क्यों न प्राप्त हुई हों।

एजेंसी ने 25 जून को जारी परामर्श में कहा, ''यह देखा गया है कि बड़े पैमाने पर मैलवेयर फैलाने के एक अभियान से व्हाट्सऐप डेस्कटॉप और व्हाट्सऐप वेब उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।''

कैस्परस्की और सिक्योरलिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरा पैदा करने वाले लोग हैक किए गए व्हाट्सऐप अकाउंट का इस्तेमाल करके सीधे पीड़ितों को खतरनाक फाइल भेजते हैं। इससे मैसेज असली लगते हैं और सफल हमले की आशंका काफी बढ़ जाती है।

सीईआरटी-आईएन ने कहा, ''हमलावर पहले से हैक किए गए व्हाट्सऐप अकाउंट का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ता के परिचित लोगों को खतरनाक फाइल भेजते हैं। जान पहचान वाले व्यक्ति के नंबर से मैसेज आने की वजह से इन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति फाइल को खोलने के लिए जल्दी तैयार हो सकते हैं।'' मैलवेयर हमले में सफलता मिलते ही साइबर अपराधी उपकरण का रिमोट एक्सेस (उपकरण पर नियंत्रण) हासिल कर सकते हैं, धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए निजी जानकारी चुरा सकते हैं। इन सब से लोगों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

ईरान से सस्ते दामों में तेल और गैस आयात करने पर विचार कर रहा पाकिस्तान

लाहौर/भाषा। अमेरिका की तरफ से ईरान को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए 60 दिन की छूट देते हुए प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद पाकिस्तान अब तेहरान से सस्ता तेल तथा गैस आयात करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान-अमेरिका संघर्ष समाप्त होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल हुई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट आई है। उन्होंने कहा, हम ईरान से सस्ते दामों में तेल और गैस आयात करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मलिक ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों और दायित्वों के अनुसार काम करना जारी रखेगी।

बाघ संरक्षण से वन, जलस्रोत और जैव विविधता भी सुरक्षित होती है : भूपेंद्र यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे वन, जलस्रोत और समृद्ध जैव विविधता का भी संरक्षण होता है।

यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 46 से बढ़कर 58 हो गई है।

यादव ने अलवर में 'बाघों के पुनर्वास : अवसर और चुनौतियां' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बाघ संरक्षण तथा 'प्रोजेक्ट चीता' से संबंधित तीन प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि बाघों का संरक्षण उन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा से भी जुड़ा है, जिनमें वन, जलस्रोत और समृद्ध जैव विविधता शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सरिस्का बाघ पुनर्वास कार्यक्रम को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह दुनिया का पहला सफल वैज्ञानिक बाघ पुनर्वास कार्यक्रम है, जिसके तहत उस क्षेत्र में बाघों को फिर से बसाया गया, जहां यह प्रजाति स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंधन, समर्पित संरक्षण प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के कारण यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर प्रजातियों के पुनर्वास का सफल उदाहरण बन गया है।

यादव ने कहा कि 2005 में स्थानीय स्तर पर बाघों के विलुप्त हो जाने के बाद सरिस्का ने उल्लेखनीय पुनरुत्थान किया है और आज वहां 56 बाघ हैं।

देश में बाघ संरक्षण की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या 46 से बढ़कर 58 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 2022 तक जंगलों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।

यादव ने कहा कि पन्ना और सरिस्का में बाघों का सफल पुनर्वास स्थानीय समुदायों के सहयोग और सक्रिय भागीदारी के कारण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभयारण्य में सामुदायिक सहयोग का अपेक्षित स्तर नहीं मिलने के कारण ऐसी सफलता नहीं मिल सकी। उन्होंने 'प्रोजेक्ट चीता' की सफलता में भी स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें देश के विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों के क्षेत्रीय निदेशक, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल हुए।

कार्यशाला में बाघों के पुनर्वास और सक्रिय प्रबंधन के लिए विज्ञान-आधारित रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

समुद्र से आकाश तक भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में निर्मित सी-295 विमान की पहली उड़ान और सतह पर हमला करने वाली लंबी दूरी की स्वदेशी क्रूज मिसाइल (एलआरएलएसीएम) के सफल परीक्षण का उल्लेख करते हुए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश की कई उपलब्धियों को रविवार को रेखांकित किया।

मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि देश ने जून में विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि सी-295 विमान भारत में बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''ऐसे 40 विमान यहीं भारत में बनाए जा रहे हैं और इससे एमएसएमई तथा वैमानिकी क्षेत्र को नई मजबूती मिल रही है।'' उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत में निर्मित पहले सी-295 सैन्य परिवहन विमान ने 10 जून को सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की थी। भारतीय वायुसेना लगभग 21,935 करोड़ रुपये की लागत से 56 सी-295 परिवहन विमान खरीद रही है। इनमें से 40 विमानों को 'टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड' द्वारा एयरबस के सहयोग से वडोदरा स्थित निर्माण केंद्र में तैयार किया जाएगा। मोदी ने कहा कि देश ने जून में कुछ अन्य ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं, जो हर नागरिक को गर्व से भर देती हैं। उन्होंने कहा, ''हाल में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन पोतों के डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है।'' प्रधानमंत्री ने कहा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने एलआरएलएसीएम का भी जून में सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा, ''दूसरे शब्दों में कहें तो समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।'' डीआरडीओ ने 15 जून को ओडिशा के तट के पास एलआरएलएसीएम का सफल उड़ान परीक्षण किया था। यह पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है और इसकी सभी उप-प्रणालियां डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक साझेदारों ने विकसित की हैं।

मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए कुछ समय तक सोना नहीं खरीदने, विदेश में छुट्टियां मनाने से बचने और साझा वाहन से यात्रा करने की उनकी अपील मानने के लिए कार्यक्रम के दौरान नागरिकों का आभार जताया। उन्होंने कहा, ''मैं देश के प्रत्येक नागरिक का आभारी हूं। उन्होंने न केवल मेरी अपील का समर्थन किया, बल्कि वे हर तरह से सक्रिय सहयोग भी कर रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त खेती अपनाने, अपनी कृषि भूमि की रक्षा करने और प्राकृतिक उर्वरकों का अधिकतम इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया था। मोदी ने युवाओं को अपनी विरासत से जोड़े रखते हुए नई प्रौद्योगिकी के लिए तैयार करने की एक पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कृत्रिम मेधा और डेटा विज्ञान में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।

नितिन नवीन ने भाजपा कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में 'डबल इंजन' सरकार के लिए जुटने का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। राज्य गठन के 12 साल बाद भी तेलंगाना आंदोलन के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में 'डबल इंजन' सरकार स्थापित करने के लिए जी-जान से जुटने का आह्वान किया। तेलंगाना की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नवीन ने हैदराबाद से डिजिटल माध्यम से राज्य में भाजपा की नौ जिला इकाइयों के कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और अन्य जगहों पर नगर निगम के आगामी चुनावों में भाजपा कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना होगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की।

नवीन ने कहा कि अगर 'विकसित भारत' का सपना सच करना है, तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए। उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी सरकार केंद्र की योजनाओं के जरिए तेलंगाना के लोगों की सेवा कर रही है। लेकिन, मुझे पता है कि जब तक 'डबल इंजन' सरकार नहीं बनती, तब तक तेलंगाना को विकास की उस राह पर नहीं लाया जा सकता, जिसके लिए राज्य का सपना देखा गया था।'' भाजपा अध्यक्ष ने याद दिलाया कि जब 1984 में लोकसभा में पार्टी की सिर्फ़ दो सीट थीं, तो उनमें से एक तेलंगाना से थी। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि भाजपा इस राज्य के लिए बाहरी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा धीरे-धीरे देश के हर राज्य में जीत रही है तथा वह दिन दूर नहीं जब पार्टी तेलंगाना में भी कामयाब होगी। नवीन ने कहा कि भाजपा ने पिछली बीआरएस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिला।

कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी हमेशा लोगों के हितों से समझौता करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को सिर्फ़ भाजपा के कार्यकर्ता ही हरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता का उदाहरण देते हुए, नवीन ने पार्टी महासचिव सुनील बंसल से तेलंगाना में दोगुनी कोशिश करने की अपील की। बंसल ने बंगाल में भाजपा के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी।

नवीन ने दो जून को दिल्ली में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में अपनी भागीदारी को याद करते हुए कहा कि जिस सपने के लिए राज्य का दर्जा हासिल किया गया था, वह पूरा नहीं हुआ है।

नवीन ने ''तेलंगाना के गठन में दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज की भूमिका को भी याद किया, जिन्होंने संसद में इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया था।''

बच्चे बोझ नहीं, बल्कि समृद्धि का स्रोतः मुख्यमंत्री नायडू

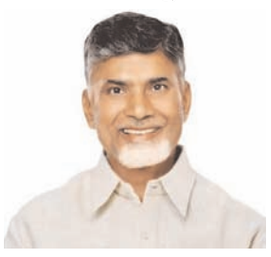

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को पल्स पोलिया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर अमरावती स्थित अपने कैंप कार्यालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई।

इस अवसर पर अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए नायडू ने संयुक्त परिवार प्रणाली को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के पालन-पोषण में पिताओं को भी समान जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अब बोझ के रूप में नहीं, बल्कि धन और समृद्धि के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, पतियों और परिवार के अन्य पुरुषों को बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश और देखभाल करने को केवल माताओं की ही जिम्मेदारी नहीं माना जाना चाहिए। अतीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पहले के समय में दादा-दादी और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के पालन-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार प्रणाली ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में अत्यधिक योगदान दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस व्यवस्था की वापसी होगी।

उद्धव ने बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की, कहा- दल-बदल एक बड़ी साजिश का हिस्सा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

परभणी/भाषा। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को पार्टी के उन छह सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की जो हाल ही में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका पाला बदलना एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था।

परभणी में एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को दल-बदल के मामले में कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का केंद्रीय नेतृत्व सुनियोजित तरीके से अपने ही राज्य के नेताओं के 'पर कतर रहा है'। उन्होंने राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उसे 'बाबर जनता पार्टी' करार दिया। उन्होंने सवाल किया, ''बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। अब एक 'बाबर जनता पार्टी' नए बने मंदिर को लूटने आई है। उनमें क्या अंतर है?'' ठाकरे ने बताया कि शिवसेना (उबाठा) के वफादार सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र सौंपकर अपना पक्ष रखने का मौका मांगा है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष द्वारा सुनवाई की तारीख पहले कर दिए जाने के बाद पार्टी सांसद अरविंद सावंत को कारगिल का अपना आधिकारिक दौरा बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा, ''अगर इस देश में कानून का राज है, तो इन छह सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। मुझे अब भी लोकसभा अध्यक्ष पर भरोसा है क्योंकि अगर वह खुद कानून का पालन नहीं करेंगे, तो दूसरों से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। हम उनके अधिकार का सम्मान करते हैं, उनकी इच्छाओं का नहीं।''

इस हफ्ते की शुरुआत में शिवसेना (उबाठा) के छह बागी लोकसभा सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सत्ताधारी शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने 2024 के आम चुनावों में भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवारों को हराया था। शिवसेना (उबाठा) ने 2024 में महाराष्ट्र में नौ लोकसभा सीट जीती थीं। ठाकरे ने उन चुनाव क्षेत्रों का दौरा किया है जिनका प्रतिनिधित्व बागी सांसद करते हैं। बागी सांसदों में से एक, संजय जाधव, परभणी से हैं।

वधावन बंदरगाह अगले 30 वर्षों तक महाराष्ट्र और भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा: फडणवीस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि पालघर जिले में प्रस्तावित वधावन बंदरगाह भारत की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित होगा और यह अगले तीन दशकों तक राज्य एवं देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

फडणवीस ने पालघर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि सरकार इस परिवर्तन प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करवाएगी। उन्होंने परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा, ''वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र और देश की अर्थव्यवस्था को अगले 30 वर्षों तक गति देगा। यह भारत की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय बनेगा। वधावन में प्रस्तावित यह बंदरगाह 10 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर है, जहां 20 मीटर प्राकृतिक गहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बंदरगाह क्षमता के लिहाज से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से लगभग तीन गुना अधिक कार्गो संभालने में सक्षम होगा और दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। फडणवीस ने कहा कि वधवन बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए 30 से 40 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और सरकार किसी भी प्रकार का बलपूर्वक अधिग्रहण नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय गांवों और मछुआरा समुदाय को विश्वास में लेकर पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। फडणवीस ने कहा इस परियोजना से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है।

लद्दाख में अवैध 'ऑफ-रोडिंग' पर सख्ती, उपराज्यपाल ने जिम्मेदार पर्यटन की अपील की

लेह/भाषा। कानून लागू करने की अपनी तरह की पहली मुहिम में, लद्दाख प्रशासन ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध 'ऑफ-रोडिंग' (सड़क से हटकर वाहन चलाने) पर कड़ा रुख अपनाया है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए चार पर्यटकों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पैंगोंग झील व अन्य संरक्षित वन्यजीव आवासों में पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के उद्देश्य से की गई यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है, जब उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पर्यटकों से लद्दाख यात्रा के दौरान जिम्मेदार व पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि 26 जून को लद्दाख के वन्यजीव विभाग ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले चार वाहनों पर 50,000 रु. प्रति वाहन का जुर्माना लगाया।

तोतापुरी आम उत्पादकों के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगा सहयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को केंद्र सरकार से तोतापुरी आम की बागवानी करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। नायडू ने कहा कि कीमतों में भारी गिरावट से किसान संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) लागू करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में 7.03 लाख टन तोतापुरी आम की खरीद के लिए 281 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी। उन्होंने किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचने से बचाने के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेप में केंद्र से सहयोग देने का भी आग्रह किया। नायडू ने कहा, ''गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार को एमआईएस के तहत पीडीपीएस को लागू करना चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। राज्य में 3.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की बागवानी होती है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 52.6 लाख टन उत्पादन होता है।

'अनुबंध के तहत भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं'

श्रीनगर/भाषा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को नौकरियों में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अनुबंध के तहत भर्ती की प्रक्रिया उनके सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने यह अनुबंध प्रक्रिया शुरू नहीं की है। यह पूर्ववर्ती सरकार के समय से चली आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे वे (पीडीपी) अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य के विभाजन के दुष्परिणामों का सामना करने के लिए हमें छोड़ गए थे। विपक्ष की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) सरकार पर लगाए गए नियम विरुद्ध नियुक्तियों के आरोपों का जवाब देने के लिए वानी ने मंत्रियों सकीना इटू और जावेद डार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।

'वीबी जी राम जी केवल केंद्रीकरण, राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की गारंटी देगा'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाए जा रहे 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबी जी-राम जी अधिनियम)' को लेकर कई राज्यों ने चिंताएं जताई हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि नया कानून केवल केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की गारंटी देगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमेशा की तरह ''प्रतिशोधी और तुच्छ'' राजनीति से प्रेरित मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति, राज्य सरकारों व अन्य संबंधित पक्षों से गहन परामर्श किए बिना ही मनरेगा को समाप्त करने का विधेयक संसद से जबरन पारित करा दिया।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि अब यह सामने आ रहा है कि मनरेगा के बदले लायी गयी और एक जुलाई से शुरू होने वाली वीबी जी राम जी योजना को लेकर कई राज्यों ने गंभीर चिंताएं जतायी हैं। रमेश ने कहा कि मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे भाजपा शासित प्रदेशों ने राज्यों पर डाले जाने वाले भारी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चार अन्य राज्य सरकारों ने खेती के व्यस्त मौसम के दौरान इस योजना में प्रस्तावित 'ब्लैकआउट अवधि' (जिस दौरान योजना के तहत काम उपलब्ध नहीं होगा) का विरोध किया है। कम से कम पांच राज्यों ने ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का अपना गृह राज्य मध्य प्रदेश भी मोदी सरकार की इस नई महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चिंता जता रहा है। उन्होंने कहा, ''मनरेगा ने संविधान से प्राप्त काम के अधिकार की गारंटी दी थी। जबकि वीबी जी-राम जी केवल केंद्रीकरण और राज्यों पर बढ़ते वित्तीय दबाव की गारंटी देगा।''

हिमाचल में अगले साल मार्च-अप्रैल में बन सकता है 'तीसरा मोर्चा' : भाजपा के पूर्व मंत्री का बयान

शिमला/भाषा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले राज्य में लंबे समय से चली आ रही दो-पक्षीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक राजनीतिक विकल्प बनाने की कोशिशें चल रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, जिन्हें 2024 में पार्टी से निकाल दिया गया था, ने कहा कि वे अलग-अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं जिनमें कांग्रेस और भाजपा में खुद को हाशिये पर महसूस करने वाले नेता भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च-अप्रैल में एक नई पार्टी शुरू की जा सकती है। उन्होंने रविवार को 'पीटीआई-भाषा' से कहा, हम बस पंचायत चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे और अब वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत फिर से शुरू होगी।

लाहौल-स्पीति सीट से पूर्व विधायक मारकंडा ने दावा किया कि बारी-बारी से सत्ता में आने वाली भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं और हाशिये पर हैं इसलिए एक ऐसी नई पार्टी की जरूरत है जो वरिष्ठ नेताओं का सम्मान और आम जनता का कल्याण सुनिश्चित करे। लाहौल और स्पीति से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 का विधानसभा उपचुनाव लड़ने के बाद मारकंडा को भाजपा से निकाल दिया गया था। चर्चा में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, पार्टी को जल्द शुरू किया जाना चाहिए।

सभी सिख विधायक और मंत्री 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होंगे : मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि बेअदबी कानून के मुद्दे पर सभी सिख विधायक और मंत्री 29 जून को अमृतसर में अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे।

मान का यह बयान सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के निर्देशों के मद्देनजर आगे की रणनीति तय करने के लिए अमृतसर में पार्टी विधायकों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक के बाद आया। उन्होंने बैठक के बाद अमृतसर में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें उनके साथ पंजाब के तीन दिवसीय दौरे पर आए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे।

मान ने जानकारी दी कि पार्टी के सिख विधायक और मंत्री अकाल तख्त के समक्ष पेश होंगे, जबकि केजरीवाल ने खुद को अमृतसर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर के निकट लव-कुश और माता जानकी को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण की बात तक सीमित रखा। मान ने अमृतसर में पत्रकारों से कहा, ''हमारे विधायक व मंत्री वहां जाएंगे और अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।'' अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने 15 जून को सभी दलों के सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को बेअदबी कानून के मुद्दे पर 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया था। गैर-सिख कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे इस मामले पर अपने विचार 29 जून से पहले लिखित रूप में प्रस्तुत करें। अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बेअदबी कानून 'जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार' (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह कानून सिख पंथ से परामर्श किए बिना बनाया गया है। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से कहा था कि वह बेअदबी कानून से उन प्रावधानों को हटाए, जो गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और 'संगत' (सिख समुदाय) की भावनाओं के खिलाफ हैं।

अयोध्या राम मंदिर चंदे में हेराफेरी की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच हो : विजयन

तिरुवनंतपुरम/भाषा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित हेराफेरी की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की।

विजयन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की खबरों को ''बेहद गंभीर'' बताया। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की आस्था और भावनाओं का लाभ उठाया, उन्होंने इसकी आड़ में एक सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी भी की। उन्होंने दावा किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासियों के संघ परिवार के संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंध थे।

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कर्तव्य है कि वह इस मुद्दे पर जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में पेश किए गए एक प्रस्ताव के जरिए केंद्र द्वारा गठित ट्रस्ट अब शक के घेरे में है।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होकर समर्थन दिया।

भूख हड़ताल शुरू करने से पहले वांगचुक ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन की शुरुआत दो मिनट का मौन रखकर की गई। वांगचुक के अनशन शुरू करने पर जंतर-मंतर पर ज्यादातर युवाओं और छात्रों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। प्रदर्शन स्थल पर कई किसान नेता भी मौजूद थे। अपने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के फैसले का कारण बताते हुए वांगचुक ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से शिक्षा उनके दिल के बेहद करीब रही है और जब युवा शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हों, तब वह चुप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, ''मुझे मजबूरी में यहां बैठना पड़ा है, मैं यह सब खुशी-खुशी नहीं कर रहा हूं। मैं इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पर बैठा हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, तो अब आप सीजेपी के साथ क्यों हैं? यहां जो मुद्दा शिक्षा का है, वह पिछले 40 वर्षों से मेरे दिल के बेहद करीब रहा है, जब से मैं एक छात्र था।'' वांगचुक ने कहा, ''मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन कभी नौकरी नहीं की, क्योंकि मेरा मानना था कि सभी पीढ़ियों के भविष्य की कुंजी शिक्षा में ही निहित है। जब कुछ युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई, तो मैं भला कैसे चुप रह सकता था? शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का जीवन संवारना और राष्ट्र को सही दिशा देना होना चाहिए''। लद्दाख में काम का उल्लेख करते हुए वांगचुक ने कहा, ''हिमालय की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस क्षेत्र से निकलने वाले जल स्रोतों पर अरबों लोगों का जीवन निर्भर करता है।''

नशीले पदार्थ मिलाकर पान मसाला बनाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने रविवार को कहा कि पान मसाला और गुटखा में नशीले पदार्थ मिलाने वाले निर्माताओं के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन उत्पादों में मादक पदार्थ मिलाए जाने की पुष्टि हुई, तो राज्य में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बेंगलूरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) के 31वें स्थापना दिवस समारोह और 'नशा मुक्त भारत' सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने छात्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों से नशामुक्त कर्नाटक के दूत बनने तथा मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में मिलकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि अब पान मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों में भी नशा पैदा करने वाले पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन उत्पादों में थोड़ी-सी मात्रा में भी कोई नशीला पदार्थ मिलाता पाया गया, तो मैं कर्नाटक में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों का बढ़ता प्रचलन समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और यह चिंता का विषय है कि बड़ी संख्या में युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। उन्होंने छात्रों से नशा विरोधी अभियान का दूत बनने और दूसरों को भी मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा, ''हमारा लक्ष्य नशामुक्त कर्नाटक का निर्माण करना है।''

शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए कई पहल शुरू की हैं और विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में नशा रोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का केंद्र है, जहां से प्रत्येक वर्ष 13,940 चिकित्सा स्नातक निकलते हैं। राज्य में 70 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें चार लाख से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रशिक्षित चिकित्सक दुनियाभर में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को जल्द ही बेंगलूरु दक्षिण जिले स्थित उसके नए परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक देश के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में से एक के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। उन्होंने सम्मेलन में शामिल छात्रों से अनुशासन बनाए रखने और संवैधानिक पदाधिकारियों के संबोधन तक कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील करते हुए कहा कि अनुशासित छात्र ही 'नशा मुक्त भारत' अभियान के सच्चे दूत बन सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथन, ''आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे'' का उल्लेख करते हुए शिवकुमार ने कहा कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए युवाओं को मादक पदार्थों से बचाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नशामुक्त कर्नाटक के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भी आश्वासन दिया।

एम्बैसी बेंगलूरु में 30 लाख वर्ग फुट कार्यालय परिसर पर 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

बेंगलूरु/नई दिल्ली। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी एम्बैसी डेवलपमेंट्स वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से किराया आय बढ़ाने की रणनीति के तहत बेंगलूरु में 30 लाख वर्ग फुट के कार्यालय परिसर के निर्माण पर 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी का मुख्य कारोबार आवास क्षेत्र में है और उसकी मौजूदगी बेंगलूरु, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) तथा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में है। एम्बैसी डेवलपमेंट्स के प्रबंध निदेशक आदित्य विरवानी ने ''पीटीआई-भाषा' से कहा कि कंपनी की मुख्य प्राथमिकता तेजी से बढ़ रहे आवास कारोबार पर बनी रहेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि कंपनी किराया आय बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय परिसंपत्तियों का भी विकास करेगी।

विरवानी ने बताया कि कंपनी बेंगलूरु में 35 एकड़ क्षेत्र में 60 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला एक बड़ा कार्यालय परिसर विकसित करेगी। उन्होंने कहा, इस परियोजना का विकास दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 30 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का निर्माण शुरू हो गया है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नशा-मुक्त भारत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शिक्षण संस्थानों, परिवारों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों तथा कानून लागू कराने वाली एजेंसियों से नशा-मुक्त भारत बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का रविवार को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान सभी शैक्षणिक परिसरों, शहरों और पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। बेंगलूरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 31वें स्थापना दिवस समारोह और 'नशा मुक्त भारत सम्मेलन' को संबोधित करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति की सेहत के लिए, बल्कि शिक्षा, उत्पादकता, परिवार के कल्याण और राष्ट्रीय विकास के लिए भी खतरा है। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, नशा मुक्त भारत का दृष्टिकोण सिर्फ मादक पदार्थों का न होना नहीं है। इसका मतलब है स्वस्थ विकल्प, सोच-समझकर लिए गए फैसले, सहयोगी परिवार और मजबूत समुदाय।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इसके छात्र उपचार, जन-जागरूकता, नीति-समर्थन और साक्ष्य-आधारित समाधानों के जरिए मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की कोशिशों में अगुवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि माता-पिता अक्सर सामाजिक बदनामी के डर से अपने परिवार में मादक पदार्थ की लत को मानने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को खत्म करने के लिए इच्छाशक्ति सबसे जरूरी है और छात्रों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि मादक पदार्थ रोधी शपथ जो उन्होंने ली है, वह उनके साथियों और समुदायों तक भी पहुंचे।

उन्होंने कहा कि जागरूकता की शुरुआत व्यक्तियों से होनी चाहिए, फिर यह कक्षा, शैक्षणिक परिसरों, शहरों और जिलों तक फैलनी चाहिए और आखिरकार इससे नशा-मुक्त कर्नाटक और नशा-मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए।

प्रौद्योगिकी, परामर्श, साथियों के सहयोग और जन स्वास्थ्य योजनाओं को शामिल करने वाले नए तरीकों की वकालत करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि शोध के आधार पर ही नीति बननी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए विद्यालयों, कॉलेजों, परिवारों, सामुदायिक संगठनों, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और नागरिक संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार नशा-मुक्त कर्नाटक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि मादक पदार्थ के कारोबार में शामिल लोगों के साथ-साथ पान मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों में मादक पदार्थ मिलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेखरी सर्कल से हेब्बाल जंक्शन तक टनल रोड बनाने का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवकुमार ने रविवार को हेब्बाल जंक्शन पर किया।

अगले 50 सालों की प्लानिंग के साथ हो रहा है काम : मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

बेंगलूरु का ट्रैफिक जाम खत्म करना हमारा मुख्य मकसद

टोल-फ्री होगी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल का हुआ शिलान्यास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को हेब्बल जंक्शन पर मेखरी सर्कल से हेब्बाल जंक्शन तक बनने वाली टोल-फ्री थ्री-लेन डबल टनल रोड का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हेब्बाल अब बेंगलूरु का गेटवे बन रहा है। हमने इस इलाके में ट्रैफिक जाम से कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन हमारा अंतिम मकसद आने वाले दिनों में पूरे बेंगलूरु से ट्रैफिक जाम को पूरी तरह खत्म करना है।

टोल-फ्री होगी 2.5 किलोमीटर लंबी टनल

मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की खासियत बताते हुए कहा कि यह 2.5 किलोमीटर लंबी 'कट एंड कवर' टनल होगी, जो पूरी तरह टोल-फ्री रहेगी। इस प्रोजेक्ट को बेंगलूरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडीए-) अपने स्वयं के फंड से पूरा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि हेब्बाल से सिल्क इंस्टीट्यूट तक 17 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसे 3 से 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा।

अगले 50 सालों का विज़न और बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर प्लानिंग कर रही है। बेंगलूरु बिजनेस कॉरिडोर (पेरिफेरल रिंग रोड) में हो रही देरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट 2006 में ही हो गया होता, तो महज 2 से 3 हजार करोड़ रुपये में पूरा हो जाता। देरी के कारण अब इसकी लागत बढ़कर 24,400 करोड़ रुपये हो चुकी है। इस 123 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए किसानों को अच्छा मुआवजा, टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) और एफएआर दिया गया है।

विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री का तंज

अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों (बीजेपी और जेडीएस) पर तीखा हमला बोला। कचरा प्रबंधन और टेंडर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए 10,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक तो टेंडर भी नहीं हुआ है और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। शायद 10,000 करोड़ रुपये रखने के लिए 20 बड़े शेड की जरूरत पड़ेगी। हम विपक्ष की आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिए। अकबर और बीरबल का किस्सा सुनाते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा, विपक्षी पार्टियां सिर्फ हाथ मल रही हैं और अपने लिए डॉक्टर ढूंढ रही हैं क्योंकि जनता ने उन्हें मौका नहीं दिया। जनता ने हमें 136 सीटें देकर सेवा का मौका दिया है और वोटर ही हमारे भगवान हैं।

बेंगलूरु के विकास के लिए 1.50 लाख करोड़ का मास्टरप्लान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने बेंगलूरु के समग्र विकास के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके अलावा, कृष्णा बायरे गौड़ा के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 30 से 40 लाख परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी के कानूनी रिकॉर्ड और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने तुंगभद्रा बांध के गेट की मरम्मत और कावेरी जल विवाद जैसे मामलों का जिक्र करते हुए भरोसा दिलाया कि आलोचनाओं के बावजूद सरकार का काम जमीन पर दिखता रहेगा।

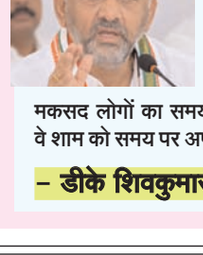

हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद लोगों का समय बचाना है ताकि वे शाम को समय पर अपने घर लौट सकें।

– डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की पोलियो टीकाकरण का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करने की अपील

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को सभी माता-पिता से पांच वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर दिलाने की अपील की। शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को विकलांगता से बचाने और भारत की पोलियो-मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिवकुमार ने बेंगलूरु में अपने आवास से पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में इसे एक ''ऐतिहासिक कार्यक्रम' करार दिया। उन्होंने कहा, ''आज हमारी सरकार पांच वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो की खुराक दे रही है, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार न हो। हमने इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।''

शिवकुमार ने स्वास्थ्यमंत्री यू टी खादर की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरी पोती एक महीने की है। इसीलिए उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेरा घर चुना है। खादर की इच्छा है कि यह कैंपेन चीफ मिनिस्टर के घर से शुरू हो। इसीलिए उन्होंने मेरे घर से यह प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम में कुल 1,14,213 वैक्सीनेशन वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें 36,686 वैक्सीनेशन सेंटर, 988 मोबाइल सेंटर और 2,125 पॉइंट शामिल हैं। कई एनजीओ इस कैंपेन में शामिल हुए हैं। मैं देश की सेवा के इस प्रोग्राम में सहयोग करने वाले सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूं।

शिवकुमार ने कहा, ''स्वस्थ कर्नाटक और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। हमारा राज्य हर स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाता रहा है।'' उन्होंने इस अभियान में सहयोग देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों को भी बधाई दी।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई कार्यक्रम में केनरा बैंक ने लिया भाग

बेंगलूरु। इंटरनेशनल एमएसएमई डे के मौके पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई), बेंगलूरु द्वारा एक उच्च स्तरीय एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास रेगुलेटरी फ़ोरम में बैंकिंग और चड्ढए सेक्टर से जुड़े कई दिग्गज स्टेकहोल्डर्स एक साथ आए। इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अगुवाई आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने वाले लीडर्स में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता, रीजनल डायरेक्टर काया त्रिपाठी उपस्थित थे।

इस फ़ोरम में सिडबी, भारत सरकार के एमएसएमई डेवलपमेंट ऑफ़िस के प्रतिनिधि, प्रमुख कमर्शियल बैंकों के कंट्रोलिंग हेड और 100 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने हिस्सा लिया और सेक्टर की तरक्की व चुनौतियों पर चर्चा की। इस रेगुलेटरी पहल में देश के अग्रणी बैंकों में से एक, केनरा बैंक की ओर से भी मजबूत भागीदारी देखने को मिली। बैंक के शीर्ष नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक भावेन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक आर अनुराधा उपस्थित थे। इस आउटरीच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करना, एंटरप्रेन्योर्स की समस्याओं को समझना और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत बैंकिंग सुविधाओं को उन तक अधिक सुलभ बनाना है। केनरा बैंक जैसे बड़े संस्थानों की इस प्रोग्राम में मौजूदगी एमएसएमई सेक्टर के प्रति उनके प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सिद्दरामय्या ने रविवार को मैसूरु में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर आयोजित कांग्रेस की जागरूकता बैठक में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की।

वक्फ भूमि विवाद में तुष्टीकरण की राजनीति से किसानों की आजीविका खतरे में : आर. अशोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने रविवार को वक्फ भूमि का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार की 'तुष्टीकरण की राजनीति' से किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार भूमि अभिलेखों में वक्फ संबंधी प्रविष्टियां दर्ज कराकर किसानों के भूमि अधिकारों को खतरे में डाल रही है और इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की।

अशोक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि राज्य के 1.8 लाख से अधिक किसानों के 'रिकॉर्ड ऑफ राइटस, टेनेंसी एंड क्रॉप्स' (आरटीसी) में पहले ही वक्फ संबंधी प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं और इस प्रक्रिया का विस्तार कर 31 जिलों में तीन लाख आरटीसी तक इसे ले जाया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले पर श्वेतपत्र जारी करने की भी मांग की। अशोक ने कहा, ''किसानों की जमीन को वक्फ विवाद में घसीटकर कांग्रेस सरकार आखिर किसके हितों की रक्षा कर रही है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति अब उस स्तर पर पहुंच गई है, जहां यह राज्य के किसानों के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गई है।''

उन्होंने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरें गलत हैं, तो सरकार को तत्काल सही तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए। लेकिन यदि

ऐसी प्रविष्टियां वास्तव में की गई हैं, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसानों को अपनी जमीन बेचने, बैंक से ऋण लेने और स्वामित्व अधिकारों का उपयोग करने में अनिश्चितता का सामना क्यों करना पड़ रहा है। भाजपा नेता ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1.8 लाख से अधिक आरटीसी में वक्फ संबंधी प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी हैं और यह प्रक्रिया आगे बढ़कर 31 जिलों के तीन लाख आरटीसी तक पहुंच सकती है।

उन्होंने कहा कि इनमें उत्तर कन्नड़ जिले के 73,000, दक्षिण कन्नड़ के 48,000, शिवमोगा के 38,000, बेंगलुरु दक्षिण के 18,000 तथा कलबुर्गी और बागलकोट के 17-17 हजार आरटीसी शामिल हैं। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने, किसानों के आरटीसी में दर्ज सभी विवादित प्रविष्टियों की समीक्षा करने और पूरे मामले पर जनता के समक्ष श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। अशोक ने कहा, ''किसानों की जमीन और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हम किसी भी परिस्थिति में वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने नहीं देंगे।''

सिद्दरामय्या ने भाजपा पर सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

मैसूरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने रविवार को मैसुरु में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जागरूकता अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है तथा वह सत्ता के केंद्रीकरण की समर्थक है। सिद्दरामय्या ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के बजाय सत्तावादी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा, वे पिछले दरवाजे से सत्ता में आए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लोकतंत्र और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। अगर लोकतंत्र और संविधान का कोई विरोधी है, तो वह भाजपा के सदस्य हैं। सिद्दरामय्या ने आरोप लगाया कि 'एक राष्ण्ट्र, एक चुनाव' की भाजपा की वकालत उसकी सत्तावादी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा, भाजपा इस देश में सत्तावादी शासन चाहती है। यही कारण है कि वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करती है।

सिद्दरामय्या ने सवाल किया कि हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों पर ऐतिहासिक रूप से अत्याचार किसने किए। उन्होंने कहा, अब वे हिंदुत्व की बात करते हैं।

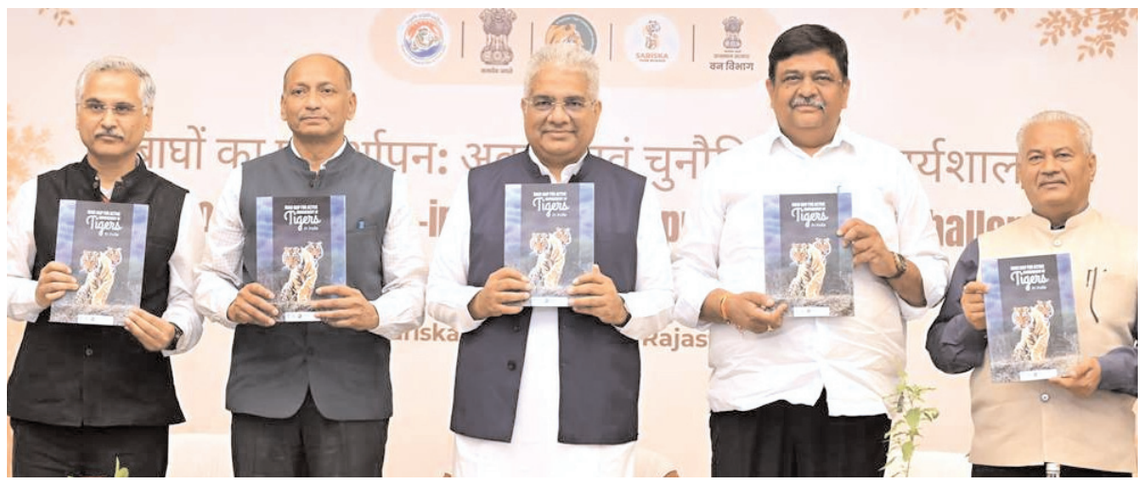

भूपेन्द्र यादव ने सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर जिले में सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एनटीसीए द्वारा अलवर में राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने तीन प्रकाशनों यथा भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन हेतु रोडमैप, भारत में बाघ पुनर्स्थापना एवं पुर्नबहाली पर पुस्तिका तथा प्रोजेक्ट चीता वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन किया तथा सरिस्का क्षेत्र की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु दो वाहन सौंपे।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत विश्व के लगभग 70 प्रतिशत बाघों का संरक्षण कर रहा है। उन्होंने सरिस्का टाइगर पुनर्स्थापना के सफलतम 18 वर्ष पूर्ण होने पर वन विभाग के कार्मिकों एवं अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं कड़ी मेहनत के बदौलत आज सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 तक पहुंची है, उम्मीद जताई की बाघों की यह संख्या जल्द 100 तक पहुंचेगी। उन्होनें कहा कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समाज और प्रकृति के सहअस्तित्व के साथ स्थानीय समुदायों के बेहतरीन पारंपरिक अभ्यासों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में टाइगर रिजर्व के साथ वहां निवासरत समुदायों यथा बांदीपुर में सोरेका समुदाय, राजाजी में गुर्जर व बकरवाल समुदाय, सिमलीपाल में संथाल समुदाय इत्यादि के सहअस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों के सहयोग से पन्ना व सरिस्का में टाइगर पुनर्स्थापना तथा कूनों में चिता पुनर्स्थापना का कार्य सफलता से संभव हुआ।

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा बाघों के संरक्षण के लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्शन, प्रबंधन, मॉनिटरिंग एवं कम्युनिटी ओरिंटेड इंटरवेंशन पर फोकस कर आगे बढाया जाए तथा नॉलेज बेस संस्थानों का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं लोगों को नेचर के साथ जोड़ने के लिए बाघ अभ्यारण के प्रवेश द्वारों पर रिजर्वस से निकलने वाली नदियों का संपूर्ण विवरण, पक्षियों एवं वन्य जीवों का विवरण, स्थानीय ट्राइबल की अच्छी प्रैक्टिस इत्यादि को दर्शाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रोजेक्ट संचालित किए गए, जिनमें प्रोजेक्ट चीता, डाल्फिन, घड़ियाल, एलिफेंट, ग्रेड इंडियन बस्टर्ड इत्यादि महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रकृति एवं टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में कैलाश सांखला सहित अन्य वन्यजीव प्रेमियों द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाघों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मानवीय मूल्यों को समाहित कर कार्य किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि टाइगर व अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जन सहयोग के साथ स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों को साथ लेकर कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की टाइगर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 32 से अधिक देशों एवं 25 हजार से अधिक लोगों ने भाग लेकर अलवर के पर्यटन को विश्व पटल पर प्रमोट करने में महती भूमिका निभाई।

जयपुर में 10 वर्षीय बालक की हत्या के आरोप में तीन नाबालिग पकड़े

जयपुर। जयपुर में 10 वर्षीय एक बालक की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 25 जून को मुहाना थाना क्षेत्र में कैश्यावाला पानी की टंकी के पास एक नाले से एक बालक का सिर कटा शव बरामद किया गया है। उसने बताया कि 14 जून से लापता इस बालक का सिर कुछ दूरी पर मिला था। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया, इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों नाबालिग बालक के परिचित एवं उसके पड़ोसी हैं।

बालक ने आरोपियों की बहन से कुछ कह दिया था, जिसे लेकर कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पार्टी देने का बहाना बनाकर बालक को एक सुनसान स्थान पर बुलाया, जहां कथित तौर पर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में तीनों नाबालिगों को निरुद्ध कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

आने वाली पीढ़ी को संस्कृति-संस्कारों से जोड़ना हमारा दायित्व : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को बगरू के निमेड़ा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है।

इससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति हमें सन्मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शिक्षा देती है।

भागवत कथा में सामाजिक जीवन, परिवार और समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के दायित्वों का विस्तृत वर्णन है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसका अनुसरण करने से परिवार में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण बनता है तथा समाज में सद्भाव और संस्कारों का विकास होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति प्रकृति को पूजनीय मानती है। हम नदियों, पर्वतों, वृक्षों और गौ माता की पूजा करते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि आने वाली पीढ़ी को संस्कृति, संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित कराना हम सभी का दायित्व है, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री का साफा पहनाकर और गौ माता का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक कैलाश वर्मा, संगरिया धूणी से ओमदास जी महाराज एवं कथावाचक साध्वी सुभद्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता की ताकत को बताया भारत की बड़ी पूंजी : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के '135वें संस्करण' में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा एवं भारतीय वन सेवा परीक्षा-2025 में चयनित राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री निवास पर इस कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, वैश्विक परिस्थितियों के बीच संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कार पूलिंग एवं प्राकृतिक खेती को मिल रहे बढ़ावे, महाराष्ट्र के एक परिवार की विवाह अवसर पर हजारों लोगों के लिए दुर्घटना बीमा कराने की प्रेरक पहल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को मिले सुरक्षा कवच, असम में 'हरगिला' पक्षी संरक्षण के लिए महिलाओं द्वारा संचालित अभियान, नागालैंड में बच्चों और बेटियों के लिए फुटबॉल एवं फुटसल लीग, नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने तथा सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की पहल, मेघालय के जीवित रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रयासों और मध्यप्रदेश में महिलाओं द्वारा प्लास्टिक कचरे से ईको-ब्रिक्स बनाकर पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने तथा आगामी गणेश उत्सव में स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी की मूर्तियों को अपनाते हुए 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से आमजन को देश में हो रहे सामाजिक सरोकारों से जुड़े नवाचारों की जानकारी एवं उसे अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की ताकत को भारत की बड़ी पूंजी बताया है। इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।

बढ़ते शहरीकरण में चार गुना गति से सुविधाओं का विकास प्राथमिकता : झाबर सिंह खर्रा

जयपुर। प्रदेश में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप नागरिक सुविधाओं का विस्तार अब नई गति से होगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के माध्यम से राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में आगामी पाँच वर्षों में लगभग छ15,800 करोड़ की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का समावेशी विकास किया जाएगा। रविवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण आधारभूत सुविधाओं की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शहरी अवसंरचना का विकास चार गुना गति से करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के तहत हुडको के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में यूसीएफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लोकसेवक विकसित भारत के निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसेवकों से अपने सेवाकाल को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। शर्मा ने रविवार को सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा-2025 में चयनित राजस्थान के अभ्यर्थियों से संवाद किया और इस दौरान युवा अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर ही सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का सपना साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि वे अपने सेवाकाल में कर्मभूमि के साथ-साथ मातृभूमि की सेवा करें और उसके प्रति अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से युवाओं को लोकसेवक बनने का अवसर मिलता है, इसलिए वे विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के प्रयासों को गति दें। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों से आने वाली पीढ़ी को भी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने विकास का व्यापक खाका तैयार कर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से पानी और बिजली के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है।

साथ ही, उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अनुज अग्निहोत्री, पक्षाल सेक्रेटरी, प्रवीण रत्नू, अदिति अरोड़ा और अनीता सहित अन्य सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इन अभ्यर्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का प्रसारण भी सुना।

औपचारिकता साबित हो रहे हैं सरकार के सेवा शिविर : जूली

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार के सेवा शिविर औपचारिकता साबित हो रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें सुधार की मांग की है ताकि आम लोगों की परेशानी कम हो। जूली ने एक बयान में कहा, हम शुरुआत से कह रहे हैं कि भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सरकार के कार्यकाल में लोगों की शिकायत है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पर दबाव पड़ा तो हमारी कांग्रेस सरकार की तर्ज पर शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर तो शुरू किए लेकिन वो औपचारिकता साबित हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद यह स्वीकारना कि बहाने नहीं समाधान चाहिए, अपने आप में वर्तमान में जारी शिविरों की वास्तविक स्थिति बता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जानकारी लेकर इसमें सुधार करेंगे। जूली ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री समय समय पर 'फीडबैक' (सुझाव) लेंगे और जो कमियां विपक्ष व आमजन बताएंगे उसे सकारात्मक तौर पर लेते हुए सुधार करेंगे ताकि आमजन की परेशानी कम हो।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और कहा कि पोलियो से बचाव का एकमात्र प्रभावी उपाय समय पर इसकी खुराक पिलाना है व इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चे के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने पांच वर्ष तक के बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर ले जाकर उन्हें पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के बाद उन्हें चॉकलेट भी वितरित की। साथ ही, अभियान के पोस्टर 'दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार' का विमोचन किया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत रविवार (28 जून) से अगले तीन दिन (30 जून तक) के दौरान राज्य में लगभग 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी जिसके लिए 59,217 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं और 75,232 टीम का गठन किया गया है।

राजस्थान में अगले सप्ताह बारिश के जोर पकड़ने की उम्मीद

जयपुर। राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में अगले सप्ताह बढोतरी होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार राज्य के कुछ भागों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने तथा जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर व कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं रविवार सुबह तक के चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान पूर्वी भाग में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। सर्वाधिक वर्षा दानपुर (बांसवाडा) में 75.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। हालांकि इसके साथ ही राज्य में तेज गर्मी का दौर जारी है। शनिवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में रहा।

भजनलाल शर्मा ने पांचना बांध से जुड़े पक्षों के हितों को लेकर बैठक की

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांचना बांध से सम्बद्ध (हितबद्ध) पक्षों के हितों को लेकर शनिवार को यहां उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए स्थायी समाधान की दिशा में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध में आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं सुधार कार्यों के साथ ही 'लिफ्ट' सिंचाई योजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए एवं किसानों को इसका वास्तविक लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों, जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तय समय-सीमा में सभी निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार भी मौजूद थे।

राजस्थान ने 1,500 सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान ने लगभग 1,500 सरकारी स्कूलों में 'खुशीशाला' पहल शुरू करके प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी) की ओर से प्रदेश के करीब 1500 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 'खुशीशाला' पहल प्रथम चरण में शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया कि 'खुशीशाला' पहल ने राजस्थान को भारत का पहला ऐसा राज्य बना दिया है, जिसने प्राथमिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य और वेलबीइंग (खुशहाली व मानसिक स्वास्थ्य) कार्यक्रम लागू किया है।

उन्होंने बताया, वर्ष 2024 में सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में खुशीशाला का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, इसमें 120 शिक्षकों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि इस पायलट कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम सामने आए। इसमें 53 प्रतिशत विद्यार्थियों में सामाजिक-भावनात्मक कौशलों में सकारात्मक सुधार देखा गया, जबकि बालिकाओं में यह सुधार 69 प्रतिशत तक पहुंचा।

उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों का सबसे बड़ा फायदा

यह हुआ कि बच्चों का मानसिक स्तर मजबूत हुआ है। साथ ही बच्चों में पढ़ाई का तनाव कम हुआ और बच्चे खेल-खेल में पढ़ाई का आनंद लेने लगे। निदेशक ने बताया कि पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद वर्ष 2025 में तकनीकी सहयोगी संस्था क्षमतालय फाउंडेशन के साथ मिलकर 165 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसमें तीन दिन का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और 60 घंटे का ऑनलाइन शिक्षण शामिल था। इसके अलावा राजस्थान की 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट्स) में 40-40 शिक्षकों सहित कुल 1320 शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 'खुशीशाला' पहल का विस्तार करते हुए पंचायत स्तर पर कुल 11,305 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

साथ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षणों के माध्यम से राज्य के 649 पीएम विद्यालयों तक भी यह पहल पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर तथा पीएम विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के उपरांत राज्य के 12,000 से अधिक विद्यालयों में कम से कम एक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होगा, जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों तक खुशीशाला की अवधारणा और गतिविधियों को प्रभावी रूप से पहुंचाएगा।

आरएससीईआरटी के अनुसार, 'खुशीशाला' पहल का उद्देश्य बच्चों में भावनात्मक सशक्तता, सामाजिक विकास और जीवन कौशल का विकास करना है।

इसमें विद्यार्थियों के साथसाथ शिक्षकों के भी मानसिक स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। पहल के तहत बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, वहीं शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों की मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को समझने के लिए तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत शिक्षकों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक अपने मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य पर कार्य करते हैं। साथ ही 21 दिनों का एक आडियो कार्यक्रम भी दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के 10 जिले बाढ़ की चपेट में, मृतक संख्या तीन हुई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश में बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद तलाशी एवं बचाव अभियान में पापुम पारे जिले में एक और शव मिलने के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की खबरें हैं, जिससे घर जलमग्न हो गए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव और निकासी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने कहा कि दस जिले – केई पन्योर, पापुम पारे, क्रा दादी, कुरुंग कुमेय, लोअर सुबनसिरी, कामले, ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी सियांग, लेपाराडा और निचला सियांग – बारिश से प्रभावित हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार सुबह तक अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव दानी सुलु ने बताया कि सौरभ कुमार खारवार का शव केयी पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पूसा क्षेत्र से लगभग 35 किलोमीटर दूर हवा कैंप के पास मिला। शव को वापस लाने के लिए एक बचाव दल रवाना किया गया है।

बुधवार सुबह लगातार बारिश के कारण केयी पैन्योर ज़िले में अचानक आई बाढ़ (फ़्लैश फ़्लड) की चपेट में आने से पांच लोग लापता हो गए थे। एक और शव मिलने के साथ ही अब तक तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि दो अन्य लापता हैं। बुधवार को 35 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था जबकि शनिवार को एक अन्य महिला का शव मिला था। रविवार को तलाशी अभियान को पांच दिन हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जारी तलाशी एवं बचाव अभियान को और मज़बूत करने के लिए रविवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 23 और जवान केयी पन्योर ज़िले के लिए रवाना हुए।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर रुख स्पष्ट करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव : मुख्यमंत्री योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हाथरस/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश खुद को धार्मिक साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें मथुरा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर बोलना चाहिए।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी जांच के बीच अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा था कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और उनकी पार्टी सत्ता में आने पर अयोध्या को एक ''बेमिसाल'' धार्मिक एवं पवित्र नगरी के रूप में विकसित करेगी।

हाथरस में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, ''अखिलेश जी, अयोध्या को तो रामभक्तों ने संवार दिया। आप मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने आपको धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा-वृंदावन पर खुलकर बोलिए, श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलिए। यह भी कहिए कि श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की तर्ज पर ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का अभियान चलना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''भगवान श्रीकृष्ण की

जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन आपमें (अखिलेश में) यह कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने एक वर्ग के सामने घुटने टेकने के अलावा प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा नहीं रखा।''

योगी ने कहा, ''बात अयोध्या, मथुरा और काशी के उत्थान तथा उनकी पौराणिक पहचान को सुदृढ़ करने की होनी चाहिए। लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम मत करिए। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''अयोध्या की अपनी पहचान है और उसने दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।''

मुख्यमंत्री ने कहा, ''अखिलेश यादव कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे, आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? अपना इतिहास देखिए। रामभक्तों पर गोली आपके ही लोगों ने चलवाई थी। आपकी ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली चलवाई थी।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''आप (अखिलेश) भूल गए कि आपने थानों और जेलों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन तक पर रोक लगा दी थी। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज हाथरस में 22 से अधिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ है। क्या यह सपा शासन में संभव था? उनके समय में यह संभव नहीं था।''

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को आजमगढ़ में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी निंदनीय और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ''दान में गबन की खबरों के बाद सरकार को दबाव में आकर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा। हालांकि, इससे यह सवाल उठता है कि एसआईटी की रिपोर्ट एक खास व्यक्ति को ही क्यों सौंपी गई।''

ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चोरी के 316 स्मार्टफोन बरामद किए, दो आरोपी गिरफ्तार

नोएडा (उप्र)/भाषा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भारत से महंगे स्मार्टफोन चोरी कर कथित रूप से नेपाल और बांग्लादेश में बेचने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनसे कई संख्या में फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) संतोष कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने दादूपुर निवासी विजय (36) और बुलंदशहर निवासी मिथुन (28) को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी के 'आईक्यू' कंपनी के 316 स्मार्टफोन तथा वारदात में प्रयुक्त एक ऑटो रिक्शा बरामद किया है।

कुमार ने कहा, ''पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे कंटेनर और ट्रक चालकों से मिलीभगत कर नोएडा से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जा रहे महंगे मोबाइल फोन चोरी करते थे। गिरोह के सदस्य ट्रक चालकों और उन ढाबा संचालकों से भी सांठगांठ रखते थे, जहां वाहन रुकते थे।'' उन्होंने कहा, ''चोरी के मोबाइल बाद में नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में बेच दिए जाते थे।'' एडीसीपी ने बताया कि इसी गिरोह के तीन अन्य सदस्यों को थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने 21 जून को गिरफ्तार किया था और उस समय उनके कब्जे से 100 से अधिक चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। गिरोह के सदस्यों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरोह का सरगना मनोज अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, चोरी के मोबाइल विदेशों में बेचने का काम वही करता है। उसने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन दिल्ली के द्वारका थाना क्षेत्र से चोरी किए गए थे और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह अब तक करीब 4,000 मोबाइल फोन चोरी कर चुका है।

विहिप ने अयोध्या को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वादे की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस वादे को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर अयोध्या नगरी को 'सियाराम धाम' के रूप में विकसित करने की बात कही थी। विहिप का कहना है कि मंदिर नगरी को लेकर उनकी सरकार का पिछला रिकॉर्ड भरोसे लायक नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी इस संस्था ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर से हजारों करोड़ रुपये की कीमती चीजें गायब हो गई हैं।

विहिप का दावा है कि ऐसे बयानों का मकसद अशांति फैलाना और देश का माहौल खराब करना है। विहिप की यह प्रतिक्रिया यादव के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर के चंदे में कथित हेराफेरी की चल रही जांच के बीच कहा था कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि अगर राज्य में समाजवादी पार्टी अगली सरकार बनाती है, तो वह अयोध्या नगरी को एक 'बेमिसाल' पवित्र शहर के रूप में विकसित करेंगे।

यह प्रतिक्रिया तब भी आई, जब कांग्रेस ने राम मंदिर को प्राप्त दान में कथित हेराफेरी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और कथित 'घोटाले' के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की बात कही। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने यादव के चुनावी वादे को भगवान राम के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करार देकर खारिज कर दिया।

कुमार ने 'एक्स' पर एक वीडियो बयान में कहा, ''अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अजीब बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, तो वे अयोध्या नगरी को 'सियाराम धाम'बना देंगे। चुनाव के दौरान लोग ऐसे वादे करते हैं कि अगर वे जीतेंगे, तो आसमान से तारे तोड़ लाएंगे या धरती पर स्वर्ग उतार देंगे। अयोध्या को 'सियाराम धाम' बनाने का यह वादा भी उसी श्रेणी में आता है।''

कुमार ने कहा, ''अखिलेश जी पूरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उस दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए क्या किया। उन पांच वर्षों के दौरान, न तो वे दर्शन के लिए अयोध्या आए और न ही इसके विकास के लिए कोई काम किया।''

कुमार ने कहा कि अयोध्या एक भूले-बिसरे गांव जैसी लगती थी। उन्होंने कहा कि हर जगह धूल, टूटी सड़कें और जर्जर बुनियादी ढांचा था। कुमार ने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में कोई सार्थक काम नहीं हुआ।

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''जब उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब अयोध्या में गोलियां चली थीं और कारसेवक मारे गए थे। अब वह कह रहे हैं कि वे इसे 'सियाराम धाम' बनाएंगे। लोग उनके पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, तो पाएंगे कि कुछ नहीं किया गया था।''

लखनऊ में कोल्ड स्टोरेज में लगी आग, कोई हताहत नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में रविवार सुबह एक कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उसने बताया कि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

आग लगने की सूचना दमकल विभाग को स्थानीय लोगों ने दी जिसके बाद दमकल की 12 से अधिक गाड़ियां और दो हाइड्रोलिक मशीनें मौके पर तैनात की गईं। लखनऊ-अयोध्या मार्ग स्थित इस कोल्ड स्टोरेज में दमकलकर्मियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया। कोल्ड स्टोरेज के टिन शेड के ऊपर से उठती आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं, जबकि घने धुएं के गुबार पूरे इलाके में फैल गए थे। चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा, ''इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय पुलिस उन्हें पूरा सहयोग दे रही है।'' पुलिस के अनुसार, हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से आग बुझाई गई। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि परिसर के भीतर कोई व्यक्ति फंसा न रह जाए। मिश्रा ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के चारों ओर खुला स्थान होने के कारण आग आसपास की इमारतों तक नहीं फैल सकी। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर जलते सामान से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के पीछे स्थित कॉलोनी के निवासियों को अस्थायी रूप से वहां से हटा दिया गया।

राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों के घर छापेमारी

अयोध्या (उप्र)/भाषा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों के आवासों पर रविवार को पुलिस ने एक साथ छापेमारी की। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मामले की जांच के सिलसिले में की गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस दलों ने लव कुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला और रामाशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी मनीष यादव के घर से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। पुलिस ने उसके परिजनों से बंद मकान खुलवाया। अन्य आरोपियों के घरों की भी तलाशी ली गई, जहां परिजनों से पूछताछ की गई और दस्तावेजों की जांच की गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों की संपत्ति, उनके पिछले रिकॉर्ड और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। अयोध्या की एक अदालत ने दो दिन पहले सभी आठ आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

असम में महिलाओं के 'हरगिला' पक्षी संरक्षण प्रयास का जिक्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम में किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

गुवाहाटी/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में पाए जाने वाले दुर्लभ और विशालकाय पक्षी 'हरगिला' को बचाने और उसके संरक्षण के लिए जीवविज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन तथा ग्रामीण महिलाओं के समूह द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की।

मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में 'हरगिला सेना' की संरक्षण पहल की कहानी का जिक्र किया और कहा कि इससे पता चलता है कि सही जानकारी पुरानी सोच को बदलने में मदद कर सकती है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज के 'मान की बात' कार्यक्रम में आदरणीय

नरेन्द्र मोदी जी ने असम की एक खास संरक्षण पहल के बारे में बताया। 'ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क' या 'हरगिला' को दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता था और उनके रहने की जगहों को नष्ट कर दिया जाता था, लेकिन तभी तक जब तक कि महिलाओं ने समुदाय-स्तर पर एक मिशन शुरू नहीं किया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि 'हरगिला' एक दुर्लभ पक्षी है, जो प्रकृति को साफ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन उसे लंबे समय से असम के कुछ हिस्सों में अशुभ माना जाता रहा है। उन्होंने कहा, ''लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। अक्सर, जिन पेड़ों पर 'हरगिला' के घोंसले होते थे, उन्हें काट दिया जाता था।'' बर्मन ने लोगों के मन में गहराई से बैठी गलतफहमियों को दूर करने का संकल्प लिया और महिलाओं से बात करके उन्हें विज्ञान पर आधारित तथ्य समझाए। मोदी ने कहा कि धीरे-धीरे महिलाएं 'हरगिला' को बचाने के उनके अभियान से जुड़ने लगीं और जो पक्षी कभी अशुभ मानकर भगा दिया जाता था, वह उस इलाके के गांवों की पहचान बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''हरगिला को बचाने के लिए हजारों ग्रामीण महिलाएं आगे आईं और आज उन्हें 'हरगिला सेना' के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं को सामाजिक विरोध का भी सामना करना पड़ा।''

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हुई हैक, पाकिस्तान के समर्थन में संदेश

मेरठ/भाषा। मेरठ विकास प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट हैक कर ली गई और अज्ञात हैकर ने वेबसाइट के मुख्यपृष्ठ पर कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक संदेश और नारे प्रदर्शित कर दिए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस घटना के बाद प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार, वेबसाइट खोलने पर सामान्य जानकारी के बजाय काले रंग की स्क्रीन पर आपत्तिजनक संदेश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि हैकरों ने स्वयं को 'ओवरथ्रश1337' नामक समूह का सदस्य बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही मेरठ प्राधिकरण की तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) टीम ने वेबसाइट को बहाल करने तथा सर्वर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल वेबसाइट काम नहीं कर रही है और तकनीकी दिक्कतों के दूर किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक होने का मामला संज्ञान में आया है। वेबसाइट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।

सम्राट चौधरी 'रबर स्टांप' मुख्यमंत्री हैं : तेजस्वी यादव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोपों को लेकर राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को सम्राट चौधरी को 'रबर-स्टांप' मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनमें काबिलियत की कमी है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि सरकारी खजाना खाली होने के कारण वेतन और पेंशन में देरी हुई है।

यादव ने कहा, ''राज्य एक नाजुक वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है... निधि की कमी के कारण वेतन भुगतान में देरी हुई है और सरकारी योजनाओं व विकास परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ा है। राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। कुछ चुनिंदा नौकरशाह सरकार चला रहे हैं। सम्राट चौधरी एक 'रबर-स्टांप' मुख्यमंत्री हैं... 'सम्राट चौधरी अंगूठा छाप हैं' और उनमें काबिलियत की कमी है... वह अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर काम कर रहे हैं।'' 'रबर-स्टांप' मुख्यमंत्री का आशय नाममात्र के मुख्यमंत्री से है जो खुद निर्णय नहीं लेता हो। उन्होंने दावा किया कि राज्य में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई है और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को राशि नहीं दे रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने पेंशन का भुगतान करने और कुछ योजनाओं के लिए 'आकस्मिक निधि' से 3,660 करोड़ रुपये निकाले। यादव ने कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी उपायों के लिए नियमित बजट प्रावधान करने के बजाय आपातकालीन फंड पर निर्भर है। राज्य के कथित टेंडर घोटाले पर यादव ने कहा, ''राज्य में करोड़ों रुपये के टेंडर घोटाले ने राजग नेताओं, खासकर भाजपा नेताओं की पोल खोल दी है। इससे पता चलता है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। राज्य सरकार इस घोटाले में शामिल कुछ बड़े लोगों को बचा रही है, यही वजह है कि हाल ही में आरोपपत्र दाखिल करने वाली विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) ने इस मामले में कुछ अधिकारियों समेत केवल सात लोगों के नाम शामिल किए हैं।

भाजपा सरकार बंगाल विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में जुटी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 साल के शासन को समाप्त करने के दो महीने से भी कम समय बाद भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर सकती है। इससे चुनाव के बाद की पहली बड़ी वैचारिक बहस के शुरू होने की संभावना है।

इस प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए धर्म से परे एक समान नागरिक प्रारूप बनाना है।

उम्मीद है कि यह मौजूदा बजट सत्र में चर्चा का मुख्य विषय रहेगा और पहचान, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक अधिकारों और 'पर्सनल कानून' व राज्य के अधिकार के बीच संबंधों पर व्यापक बहस का आधार बनेगा। भाजपा के लिए यह विधेयक उसके मुख्य चुनावी वादे को पूरा करने और इस लंबे समय से चली आ रही बात को दोहराने जैसा है कि सभी नागरिकों पर एक जैसे नागरिक कानून लागू होने चाहिए। वहीं विपक्ष के लिए यह सामाजिक सहमति, संवैधानिक सुरक्षा और इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या अलग-अलग समुदायों पर असर डालने वाले सुधार को बिना व्यापक बातचीत के लागू किया जा सकता है।

यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के 'संकल्प पत्र' में वादे के तहत तय की गई छह महीने की समय-सीमा से काफी पहले उठाया जा रहा है। घोषणा-पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के छह महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करेगी। उन्होंने इसे आस्था से परे कानून के सामने समानता सुनिश्चित करने के उपाय के तौर पर पेश किया था।

विश्व चैंपियनशिप का अपने देश में आयोजित होना ऐतिहासिक पल है : पीवी सिंधू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने नई दिल्ली में होने वाली बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप को भारतीय बैडमिंटन के लिए ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि अपने देश में इस खेल के सबसे बड़े खिताब के लिए मुकाबला करने का मौका इस टूर्नामेंट को और भी खास बना देगा।

भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने आधिकारिक तौर पर विश्व चैंपियनशिप के लिए 50 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है जिसका आयोजन 17 से 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। यह प्रतियोगिता 17 साल बाद भारत में वापसी करेगी और राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार इसका आयोजन होगा।

सिंधू 2019 में बासेल में खिताब जीतकर भारत की एकमात्र विश्व चैंपियन बनी थीं। सिंधू ने कहा, ''विश्व चैंपियनशिप मेरे करियर के सबसे खास टूर्नामेंट में से एक रही है। मेरे कुछ

सबसे यादगार पल, सबसे मुश्किल सबक और सबसे फक्र करने वाली उपलब्धियां इसी मंच पर मिली हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारत में अपने ही प्रशंसकों के सामने विश्व चैंपियनशिप में खेलने का मौका इसे और भी विशेष बनाता है। ऐसा मौका कम ही मिलता है जब आप घर पर विश्व खिताब के लिए मुकाबला कर सकें। मैं उस माहौल का अनुभव करने और उन सभी लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हूं जिन्होंने इतने वर्षों मेरा समर्थन किया है।'' तीस साल की सिंधू ने कहा कि इस टूर्नामेंट की मेजबानी देश में खेल के विकास को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ''भारतीय बैडमिंटन के लिए 17 साल बाद विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करना एक ऐतिहासिक पल है और यह दिखाता है कि हमारे देश में यह खेल कितनी दूर आ गया है। यह हम सभी के लिए गर्व का मौका है और मैं ऐसे टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं, जिससे मुझे उम्मीद है कि और भी युवा खिलाड़ी बड़े सपने देखने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित होंगे कि वे विश्व स्तर पर सफल हो सकते हैं।'' बीएआई अध्यक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने विश्व चैंपियनशिप की वापसी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक निर्णायक पल बताया। उन्होंने कहा, ''यह भारत की बेहतरीन स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने की क्षमता में अंतरराष्ट्रीय खेल समुदाय के बढ़ते भरोसे को भी दिखाता है।'' इस चैंपियनशिप में 55 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है जिनमें लगभग 800 खिलाड़ी, टीम अधिकारी, सहयोगी स्टाफ, तकनीकी अधिकारी और मीडियाकर्मी शामिल होंगे।

सुविचार

अनुभव एक बेहतरीन शिक्षक है, यह पहले परीक्षा लेता है और पाठ बाद में सिखाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

संकल्प से सिद्धि

'मन की बात' कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द 'संकल्प से सिद्धि' को दर्शाते हैं कि 'किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं। जब लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती है।' प्रधानमंत्री ने सत्य कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। हाल में पश्चिम एशिया में अशांति फैलने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से जो अपील की, उसका गहरा असर दिखाई दिया। जो लोग हर साल छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते थे, आज वे भारत में ही पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों ने ईंधन की बचत के लिए कई उपाय किए। ऐसे कई घर हैं जहां विवाह कार्यक्रम हुए, लेकिन उन्होंने सोना नहीं खरीदा। देशवासियों ने सोशल मीडिया पर एकता का संदेश दिया। जब समय मुश्किल हो तो परिवार के सदस्यों को इसी तरह एकजुट होना चाहिए। अगर जनभागीदारी इतनी मजबूत हो तो कोई संकट हमें अपने मकसद से डिगा नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बहादुरपुरा गांव के पेठकर परिवार की अनूठी पहल का जिक्र कर अन्य ग्रामवासियों को प्रेरणा दी है। उक्त परिवार ने घर में विवाह के अवसर पर पूरे गांव के लगभग साढ़े तीन हजार लोगों का दुर्घटना बीमा करवा दिया। इस तरह, पेठकर परिवार ने अपनी खुशियों में समस्त ग्रामवासियों को शामिल करते हुए उन्हें संबल दिया है। अगर ऐसी पहल हर गांव-शहर में होने लगे तो लोगों का जीवन कितना आसान हो जाए!

प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर इसका अक्लमंदी से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे गांवों और शहरों की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे सकता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा गांव की महिलाओं ने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने प्लास्टिक कचरे और खाली बोतलों को इकट्ठा कर उन्हें 'इको ब्रिक्स' में बदल दिया। अगर हर गांव और शहर में इको ब्रिक्स बनाने का काम शुरू हो जाए तो प्लास्टिक कचरे से निजात मिल जाए। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में अंधविश्वास पर भी जोरदार प्रहार किया है। असम में हरगिला नामक दुर्लभ पक्षी को अशुभ माना जाता था, जबकि यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन के प्रयासों के कारण अब लोगों की सोच बदल रही है। वे हरगिला से डरने के बजाय उसका संरक्षण कर रहे हैं। हालांकि यह काम आसान नहीं था। कई लोगों की रूढ़िवादी सोच इसमें बाधा बन रही थी। आखिरकार, पूर्णिमा देवी बर्मन और उनकी टीम की जीत हुई। आज हजारों लोग, जिनमें महिलाओं की बड़ी तादाद है, हरगिला को बचा रहे हैं और यह पक्षी पर्यावरण को बचा रहा है। प्रकृति में हर जीव-जंतु का महत्त्व होता है। आज कई जगह चिड़िया, तोता, मोर, बुलबुल, कौआ जैसे पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन पक्षियों पर कई लोकगीत लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि ये सदियों से हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। क्या भविष्य में ये सिर्फ किताबों और मोबाइल फोन में दिखाई देंगे? पक्षियों का संरक्षण करने के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस कराना जरूरी होता है। इसके लिए ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जाएं, जहां पक्षी अपना बसेरा बनाएं और उनकी गतिविधियों में कोई व्यक्ति व्यवधान न डाले। नागालैंड बेबी लीग भी सराहनीय पहल है। छोटे बच्चों को खेलकूद के लिए जरूर प्रेरित करना चाहिए। अगर बचपन से ही खेलकूद और योगाभ्यास की आदत डाल लें, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो भविष्य में कई बीमारियों से सुरक्षा मिल जाए।

ट्वीटर टॉक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में भारतीय संस्कृति के दुनिया भर में फैलने के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर, डोमिनिकन रिपब्लिक में कुछ लोगों ने ब्रह्मकमल डोमिनिकाना नाम की एक टीम बनाई है ।

-गजेन्द्रसिंह शेखावत

मैंने बगरू विधानसभा क्षेत्र से माननीय चङ- श्री कैलाश वर्मा जी द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया, जहाँ मुझे गहरी आध्यात्मिक अनुभूति हुई। कथा के दिव्य संदेशों ने भक्ति, श्रद्धा, जनकल्याण और सनातन संस्कृति में विश्वास को और मजबूत किया।

-भजनलाल शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मज़बूत उदाहरण पेश कर रहा है, यह साबित करते हुए कि पर्यावरण से जुड़े बड़े वादे तय समय से पहले असल दुनिया में बड़े नतीजे हासिल कर सकते हैं।

-अर्जुनराम मेघवाल

प्रेरक प्रसंग

आजादी का संकल्प

चंद्रशेखर आजाद ने मातृभूमि को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था। उन दिनों रामकृष्ण खत्री क्रांतिकारियों के साथ काम कर रहे थे। एक बार गाज़ीपुर के एक महंत बीमार थे। उन्होंने रामकृष्ण खत्री से कहा 'आपकी निगाह में यदि कोई सुशील और सच्चरित्र लड़का हो तो बताइए। मैं उसे अपना शिष्य बनाकर इस मठ की व्यवस्था उसके सुपुर्द करना चाहता हूं।' खत्री जी ने इस बात की चर्चा क्रांतिकारियों से की, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। खत्री जी ने कहा 'तुम पागल तो नहीं हो? साधु बनोगे? सिर मुंडवाना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी और सेवा भी करनी होगी। दिन-रात मठ में ही रहना पड़ेगा।' आज़ाद ने कहा'मेरे साहित्यकार भाई! मठ में काफी संपत्ति है। हमारी पार्टी को धन की बहुत आवश्यकता है। यदि धन होगा तो पार्टी बहुत मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत होगी तो देश जल्दी आज़ाद हो जाएगा। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।' खत्री जी ने पूछा'तुम्हारा परिचय किस नाम से करवाया जाए?' आज़ाद बोले'एक कवि के नाम से करवा देना, बस ।' खत्री जी ने फिर पूछा'अगर महंत जी कविता सुनाने के लिए कहने लगे तो?' आज़ाद गंभीर होकर बोले'देश की आज़ादी के लिए मैं क्रांतिकारी बन सकता हूं, तो क्या कवि नहीं बन सकता?

सामयिक

भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता का प्रश्न

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

व्यापक वैश्विक व्यवस्था में पासपोर्ट को किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता और पहचान का सबसे सशक्त प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, तो उसका पासपोर्ट ही उसकी पहचान, उसके मूल देश और उस देश के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संदर्भ में भी, आम जनता के बीच यह एक बेहद सामान्य और सुदृढ़ धारणा है कि यदि किसी के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध पासपोर्ट है, तो वह अकाट्य रूप से भारत का नागरिक है। सामान्य व्यावहारिक जीवन में यह धारणा सही प्रतीत हो सकती है क्योंकि बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड लेने या किसी गैर-सरकारी कार्य में पासपोर्ट को पहचान के सर्वोच्च दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। परंतु, जब हम इस विषय का विधिक, संवैधानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं, तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बारीक कानूनी अंतर सामने आता है। भारतीय कानून और न्यायपालिका की दृष्टि में पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का अंतिम, अकाट्य और संप्रभु प्रमाण नहीं माना जाता है। इस विसंगति को समझने के लिए हमें भारतीय कानूनी तंत्र के दो अलग-अलग स्तंभों को गहराई से देखना होगा, जिनमें पहला है पासपोर्ट अधिनियम 1967 और दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955। इन दोनों कानूनों के निर्माण के पीछे के उद्देश्य, उनके कार्यक्षेत्र और उन्हें संचालित करने वाले संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से भिन्न हैं।

इस कानूनी भिन्नता का प्राथमिक कारण दोनों दस्तावेजों के मूल उद्देश्यों में छिपा हुआ है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी होने वाला पासपोर्ट मूल रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। जब भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो वह वास्तव में भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से किया गया एक आधिकारिक अनुरोध होता है। इस दस्तावेज के माध्यम से विदेशी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को अपने देश में बिना किसी बाधा के आने-जाने की अनुमति दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे हर संभव सुरक्षा और सहायता प्रदान करें। इसके विपरीत, नागरिकता एक अत्यंत गंभीर, स्थाई और संवैधानिक दर्जा है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। नागरिकता का अर्थ केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज का होना नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और राज्य के बीच एक संप्रभु विधिक संबंध को दर्शाता है। यह संबंध व्यक्ति को देश के भीतर मतदान करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण, सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या न्यायाधीश बनने की योग्यता प्रदान करता है। एक यात्रा दस्तावेज किसी व्यक्ति को इतने व्यापक और संप्रभु अधिकार अकेले अपने दम पर प्रदान नहीं कर सकता। इस विषय का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू यह है कि पासपोर्ट एक व्युत्पन्न यानी द्वितीयक दस्तावेज है। इसका अर्थ यह है कि पासपोर्ट का निर्माण अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि यह कुछ प्राथमिक और मूल दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, तो वह अपनी पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज संलग्न करता है। पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकरण इन दस्तावेजों की सत्यता की जमीनी जांच करने के लिए पूरी तरह से स्थानीय पुलिस प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अब यदि कोई विदेशी नागरिक या अवैध घुसपैठिया देश में प्रवेश करने के बाद अनुचित साधनों का उपयोग करके, जाली दस्तावेजों के सहारे या प्रशासनिक त्रुटियों का लाभ उठाकर एक नकली जन्म प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र बनवा लेता है, तो उसी आधार पर उसका पासपोर्ट भी जारी हो सकता है। कानून का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि किसी इमारत की नींव ही अवैध या जाली है, तो उस पर खड़ी की गई पूरी इमारत कभी वैध नहीं हो सकती। यदि भविष्य में कभी यह पता चलता है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जमा किए गए मूल दस्तावेज फर्जी थे, तो वह पासपोर्ट तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है। यही कारण है कि अदालतें पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम सुबूत नहीं मानतीं, क्योंकि इसकी वैधता पूरी तरह से उन प्राथमिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर टिकी होती है जिनके आधार पर इसे बनाया गया था।

भारतीय न्यायपालिका ने भी समय-समय पर इस विधिक स्थिति को अत्यंत स्पष्टता के साथ परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई ऐतिहासिक निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि पासपोर्ट को केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई विवाद न हो, तब तक पहली नजर में पासपोर्ट धारक को भारतीय माना जाएगा, लेकिन कानूनी चुनौती की स्थिति में यह नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर देश की संप्रभुता या सुरक्षा के लिहाज से कोई कानूनी सवाल खड़ा होता है, तो वह व्यक्ति केवल अपना पासपोर्ट दिखाकर जांच से बच नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, उस व्यक्ति पर यह साबित करने का विधिक भार होता है कि वह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार भारत का नागरिक है। भारत के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में, जैसे असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की तैयारी के दौरान, यह व्यावहारिक रूप से देखा गया कि कई व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए वर्ष 1971 या उससे पहले के अपने पूर्वजों के मूल भू-राजस्व रिकॉर्ड, वंश वृक्ष और जन्म से जुड़े प्राथमिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़े थे।

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) इस पूरी कानूनी व्यवस्था की धुरी है। इस विशिष्ट धारा के अनुसार, यदि कभी भी यह प्रश्न या विवाद उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति ने कब, कैसे और किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त की है, या क्या उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, तो इस विषय पर निर्णय लेने का अनन्य और अंतिम अधिकार केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण के पास होता है, जो कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय है। देश के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता का न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्धारण करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता है। उनका कार्य केवल प्राप्त आवेदनों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यात्रा दस्तावेज जारी करना है। इसलिए, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज उस संप्रभु दर्जे का स्थान नहीं ले सकता जिसका फैसला करने की शक्ति संविधान ने केवल देश की कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर को दी है।

इसके अलावा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के नियम अत्यंत कड़े और समयबद्ध हैं। उदाहरण के लिए, धारा 5 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार, धारा 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए किसी विदेशी नागरिक को पिछले 14 वर्षों में से कम से कम 11 वर्ष भारत में बिताने होते हैं और आवेदन की तारीख से ठीक पहले 1 वर्ष लगातार भारत में रहना पड़ता है। यद्यपि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसमें एक विशेष रियायत जोड़ी गई, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए विशिष्ट पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इस 11 वर्ष की अवधि की शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इन सभी जटिल ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैधानिक तथ्यों की गहन जांच करने का एक विस्तृत तंत्र केवल गृह मंत्रालय के पास होता है। पासपोर्ट कार्यालय के पास इतनी व्यापक न्यायिक जांच करने की न तो व्यवस्था होती है और न ही उनका यह उद्देश्य होता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों और वैश्विक संधियों के आलोक में भी इस स्थिति की पुष्टि होती है। भारत का संविधान एकल नागरिकता के सिद्धांत पर काम करता है और यहां दोहरी नागरिकता की स्पष्ट मनाही है। संविधान का अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में, भले ही उस व्यक्ति के पास भौतिक रूप से भारत का पासपोर्ट मौजूद हो और उसकी वैधता तिथि में कई वर्ष शेष हों, वह कानून की नजर में भारत का नागरिक नहीं रह जाता। यदि वह नागरिकता समाप्त होने के बाद भी उस भारतीय पासपोर्ट का उपयोग यात्रा के लिए करता है, तो वह एक गंभीर विधिक अपराध की श्रेणी में आता है। यह तथ्य इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पासपोर्ट केवल नागरिकता के अधिकार का एक दृश्य माध्यम मात्र है, वह स्वयं नागरिकता का सृजक या शाश्वत रक्षक नहीं है।

अंततः, देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और जनसांख्यिकीय स्थिरता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह अनिवार्य है कि नागरिकता जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय का निर्धारण केवल उन अपरिवर्तनीय मूल दस्तावेजों और वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही किया जाए जो पूरी तरह से अकाट्य हों। इसी विधिक और प्रशासनिक दूरदर्शिता के कारण, भारतीय पासपोर्ट को पहचान और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सर्वोपरि दस्तावेज मानते हुए भी, देश की नागरिकता के अंतिम और निर्विवाद साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

नजरिया

कबीर : भारतीय चेतना के महासूर्य और अमर गायक

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

कबीर के देहावसान के समय उनके पार्थिव शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ। किंवदंती है कि जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर के स्थान पर फूल मिले। यह घटना प्रतीक है कि कबीर किसी एक धर्म, संप्रदाय या समुदाय के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के संत थे। संत कबीर ने अपने जीवन और वाणी से यह सिद्ध किया कि मनुष्य का वास्तविक धर्म प्रेम, सत्य, करुणा और आत्मबोध है।

भारतीय संत परंपरा में यदि किसी एक संत ने धर्म, समाज, अध्यात्म और मानवीय चेतना को सबसे अधिक झकझोरा, तो वह नाम है-संत कबीर। वे केवल एक कवि, संत या समाज-सुधारक नहीं थे, बल्कि भारतीय आत्मा की उस जागृत चेतना के प्रतीक थे, जिसने मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि दी। कबीर भारतीय अध्यात्म के ऐसे महासूर्य हैं, जिनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक, प्रेरक और क्रांतिकारी है, जितनी छह सौ वर्ष पूर्व थी। आज जब संसार हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक विभाजन, उपभोक्तावाद, मानसिक तनाव और नैतिक पतन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब कबीर की वाणी मानवता के लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है। कबीर का समूचा चिंतन मनुष्य को स्वयं से जोड़ने, समाज को समरस बनाने और धर्म को आडंबरों से मुक्त कर उसके मूल स्वरूप तक पहुंचाने का प्रयत्न है।

कबीर का अवतरण ऐसे समय में हुआ, जब भारतीय समाज अनेक प्रकार की रूढ़ियों, कर्मकांडों, जातीय विभाजनों और धार्मिक पाखंडों में उलझा हुआ था। एक ओर मुस्लिम शासकों की धर्मांधता थी, दूसरी ओर हिंदू समाज कर्मकांड और बाह्याचार के बोझ तले दबा हुआ था। धर्म का वास्तविक स्वरूप कहीं खो गया था। ऐसे संक्रमणकाल में कबीर ने निर्भीक स्वर में उद्घोष किया- पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।' कबीर ने स्पष्ट किया कि धर्म का सार ज्ञान, प्रेम, करुणा और आत्मानुभूति में है, न कि बाहरी कर्मकांडों में। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों की सीमाओं को पार करते हुए मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा की खोज का संदेश दिया। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अनुभव के संत थे। उन्होंने स्वयं कहा- मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी।' उनकी वाणी किसी ग्रंथ, शास्त्र या परंपरा की दास नहीं थी। उन्होंने जो कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा। यही कारण है कि उनकी वाणी में अद्भुत प्रामाणिकता और जीवन-सत्य का तेज दिखाई देता है। कबीर निरंतर आत्म-परीक्षण के पक्षधर थे। उनका प्रसिद्ध दोहा-'बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।' आज के समय में भी उतना ही सार्थक है। वर्तमान समाज में दूसरों की आलोचना, निंदा और दोषारोपण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कबीर हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन का मार्ग दिखाते हैं।

संत कबीर सर्वधर्म समभाव के सशक्त प्रवक्ता थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की संकीर्णताओं की आलोचना की, लेकिन किसी धर्म का विरोध नहीं किया। उनका विरोध केवल अंधविश्वास, पाखंड और कट्टरता से था। उन्होंने कहा-'कंकर-पत्थर जोड़ि के मस्जिद लई बनाय। ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाय।' और दूसरी ओर-'पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहार। ताते तो चाकी भली, पीस खाय संसार।' इन दोहों का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की आलोचना नहीं, बल्कि मनुष्य को बाहरी आडंबरों से ऊपर उठाकर आंतरिक साधना की ओर ले जाना था। आज जब धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव विश्व के अनेक देशों में संकट का कारण बने हुए हैं, तब कबीर का संदेश-'अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे' मानवता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

कबीर ने जाति-पांति की संकीर्णता को भारतीय समाज की बड़ी कमजोरी माना। उन्होंने सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना का प्रयत्न किया। उनका प्रसिद्ध दोहा-'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान।' आज भी सामाजिक समरसता का आधार बन सकता है। कबीर ने मनुष्य की पहचान उसके कर्म, ज्ञान और चरित्र से करने की बात कही। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक ऊंचाई किसी जाति या वर्ग की बपौती नहीं है। एक सामान्य जुलाहा होकर भी वे भारतीय संत परंपरा के शिखर पुरुष बने। कबीर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता केवल जंगलों, आश्रमों और मठों तक सीमित नहीं है। उन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कीं। उन्होंने संसार से पलायन नहीं किया, बल्कि संसार में रहकर सत्य, सादगी, श्रम, ईमानदारी और संतत्व को साधा। आज जब जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकता बढ़ती जा रही है, तब कबीर का जीवन-संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि परिवार और समाज के बीच रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है।

इक्कीसवीं सदी का मनुष्य तकनीकी रूप से समृद्ध होने के बावजूद भीतर से असुरक्षित, अकेला और तनावग्रस्त है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति और उपभोक्तावाद के इस युग में मनुष्य अपने भीतर की शांति खोता जा रहा है। ऐसे समय में कबीर का यह संदेश नई दिशा देता है-'माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।' कबीर हमें बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक परिवर्तन का महत्व समझाते हैं। वे बताते हैं कि वास्तविक क्रांति मनुष्य के भीतर घटित होती है। पर्यावरण संकट, हिंसा, असहिष्णुता और नैतिक पतन के इस दौर में कबीर की करुणा, सह-अस्तित्व और सादगी की जीवन-दृष्टि मानव सभ्यता को नई राह दिखा सकती है। कबीर की वाणी किसी एक युग की नहीं, बल्कि समस्त मानवता की धरोहर है। उनकी साखियां, सबद, रमैनी, बीजक और उलटबांसियां आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनकी भाषा सहज, लोकजीवन से जुड़ी और अत्यंत प्रभावशाली है। कबीर स्वयं अशिक्षित माने जाते हैं, किंतु उनकी वाणी में जीवन का ऐसा गहन दर्शन है, जो बड़े-बड़े विद्वानों को भी विस्मित कर देता है। इसीलिए उन्हें ज्ञान का सूरज' कहा गया है। उनकी वाणी केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। वह मनुष्य को भीतर तक झकझोरती है, उसके अहंकार को तोड़ती है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

कबीर के देहावसान के समय उनके पार्थिव शरीर को लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ। किंवदंती है कि जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर के स्थान पर फूल मिले। यह घटना प्रतीक है कि कबीर किसी एक धर्म, संप्रदाय या समुदाय के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के संत थे। संत कबीर ने अपने जीवन और वाणी से यह सिद्ध किया कि मनुष्य का वास्तविक धर्म प्रेम, सत्य, करुणा और आत्मबोध है।

उन्होंने समाज को नई दृष्टि, धर्म को नई दिशा और अध्यात्म को नया आयाम दिया। आज, संत कबीर जयंती के अवसर पर आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल उनके दोहों का पाठ न करें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सचमुच, कबीर भारतीय अध्यात्म के महासूर्य हैं, जिनकी ज्ञान-किरणें युगों-युगों तक मानवता का मार्ग आलोकित करती रहेंगी।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता ।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

एफएम रेडियो : समाचारों से दूर, संकट में फंसा, सुधारों की मांग कर रहा

नई दिल्ली/भाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एफएम रेडियो स्टेशन समाचार प्रसारित क्यों नहीं करते? या फिर आपके स्मार्टफोन में दूसरे देशों की तरह एफएम ट्यूनर ऐप क्यों नहीं होता? इसका जवाब है: सरकारी पाबंदियां। एफएम रेडियो उद्योग का कहना है कि ये और दूसरे नियम उनके व्यवसाय को रोक रहे हैं और अगर सरकार ने जल्द मदद नहीं की तो पूरी एफएम रेडियो संस्कृति खत्म हो जाएगी। चेतावनी के संकेत पहले ही दिखाई दे रहे हैं।

पिछले महीने, एचटी मीडिया ने घोषणा की कि वह प्रमुख बाजारों में कई एफएम रेडियो लाइसेंस सरेंडर कर देगा, जिसके चलते 15 जून को उसके पांच स्टेशन बंद हो गए। उद्योग ने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द जरूरी सुधार करे, ताकि और मीडिया कंपनियां अपने एफएम कारोबार बंद न करें; क्योंकि उन्हें पहले से ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल ऑडियो मंचों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेड एफएम की निदेशक और सीओओ निशा नारायणन ने 'पीटीआई भाषा' से कहा, ऑन-डिमांड ऑडियो की ओर वैश्विक बदलाव स्पष्ट और अच्छी तरह दर्ज है। उन्होंने कहा कि लेकिन असली सवाल यह है कि क्या एफएम उद्योग को न्यायसंगत नियामक वातावरण मिल रहा है, जिससे वह प्रतिस्पर्धा कर सके, नवाचार कर सके और बेहतर कमाई कर सके।

फिलहाल, उद्योग की चार मुख्य मांगें हैं: निजी एफएम स्टेशनों को समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारण की अनुमति देना, जो सुविधा अभी केवल ऑल इंडिया रेडियो को मिली हुई है; रेडियो सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना; स्मार्टफोन निर्माताओं को डिवाइस में एफएम रिसीवर अनलॉक करने की अनुमति देना; और एक ऐसा मॉडल लागू करना जिसके तहत रेडियो कंपनियां पुरानी नीलामी कीमतों से जुड़े शुल्क के बजाय अपनी वास्तविक कमाई का एक निश्चित प्रतिशत लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार को दें। लाखों भारतीयों के लिए एफएम रेडियो रोज का साथी रहा है। चाहे कार्यालय आने-जाने का समय हो, घर हो, कार हो या छोटे शहर। हर जगह यह मनोरंजन और जानकारी पाने के सबसे आसान तरीकों में से एक बना हुआ है। इंटरनेट-आधारित ऑडियो मंचों के विपरीत रेडियो बिना डेटा कनेक्शन के काम करता है और बिजली जाने या नेटवर्क में बाधा होने पर भी श्रोताओं तक पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि एफएम रेडियो की चुनौतियों को सिर्फ विनियमन के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'पीटीआई भाषा' को बताया कि यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव से गुजर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बदलाव दूसरे उद्योगों में देखे गए हैं। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा तकनीकी बदलाव है जो हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि चाहे वह समाचार उद्योग हो या मनोरंजन उद्योग पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल की ओर लगातार बदलाव हुआ है और यह एफएम उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैष्णव के अनुसार, इस तरह के तकनीकी बदलाव उद्योगों का स्वरूप बदल देते हैं; इसकी तुलना मोबाइल फोन के प्रसार के बाद लैंडलाइन के चलन में कमी और पारंपरिक वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव से की जा सकती है।

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह मुंबई में महान संगीतकार शंकर महादेवन के 'भक्ति' एल्बम/कॉन्सर्ट के रेड कार्पेट इवेंट में शामिल हुए।

वेनेजुएला में भूकंप के बाद राहत सामग्री भेजी जा रही है, लेकिन इसका समय पर पहुंचना चुनौती

फ्लोरिडा। वेनेजुएला में 24 जून, 2026 को आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पहले से ही गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे इस देश में लोगों का जीवन और भी मुश्किल बना दिया है। इस आपदा से पहले ही लाखों वेनेजुएलावासी पर्याप्त भोजन, दवाइयों, ईंधन और जीवनयापन के लिए जरूरी बुनियादी सेवाएं जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब वहां पहले से कहीं अधिक लोगों को तत्काल आश्रय, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ पेयजल, भोजन और अन्य सहायता की जरूरत है।

मैं मानवीय सहायता के क्षेत्र का शोधकर्ता हूं और लातिन अमेरिका में मानवीय राहत कार्यों के प्रबंधन का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखता हूं। इन दिनों मैं आपदा क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियानों पर एक पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं। इस पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र पहले से ही यह समझ रहे थे कि लातिन अमेरिका में भूकंप और अन्य आपदाओं के बाद पुनर्वास की सफलता मजबूत स्थानीय साझेदारों, भरोसेमंद आपूर्ति व्यवस्था और सबसे अधिक प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचने पर निर्भर करती है। अब इन भूकंपों के बाद उन्हें यह भी देखने को मिलेगा कि इस तरह की त्रासदी वास्तविक समय में किस तरह सामने आती है।

क्या विदेशों में रह रहे वेनेजुएलावासी अपने परिजनों से संपर्क कर पा रहे हैं? अब भी 50,000 से अधिक लोग लापता हैं। ऐसे में शुरुआती जानकारी में मरने वालों और घायलों का जो आंकड़ा दिया गया है, वह बढ़ सकता है। मकानों के तबाह होने के बाद विस्थापित हुए लोगों की वास्तविक संख्या सामने आने भी काफी समय लग सकता है। अपने देश से बाहर रह रहे अनुमानित 80 लाख वेनेजुएलावासियों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनमें से कई अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका डर, मन में असमंजस बढ़ता जा रहा है। हालांकि, विदेशों में रह रहे वेनेजुएलावासी अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सामुदायिक समूह, गैर-लाभकारी संगठन और वेनेजुएला के नागरिकों के स्वामित्व वाले कारोबार राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए चंदा और धन जुटा रहे हैं। उनके ये प्रयास अपने वतन के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आगे बढ़कर समर्थन दिया है। कई देशों ने हेलीकॉप्टर, विमान और अन्य जरूरी रसद उपकरण भेजने की घोषणा की है, जिनका इस्तेमाल बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने और अन्य राहत एवं बचाव अभियानों में कर सकेंगे।

तेज़ रफ्तार और बेखौफ अंदाज़ में चीते के साथ दौड़ते दिखे ओरी

मुंबई/एजेन्सी। अगर हिम्मत और रफ्तार की असली परीक्षा देखनी हो, तो 'खतरों के खिलाड़ी' का हाल ही में आया प्रोमो जरूर देखिए, जिसने हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ओरी चीते के साथ रेस लगा रहे हैं, या फिर चीता उनके पीछे दौड़ रहा है? जो भी हो, इस प्रोमो में सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी इस सीजन के सबसे रोमांचक स्टंट्स में से एक का सामना करते नजर आ रहे हैं। ट्रैक पर चीते के साथ उनकी दौड़ ने प्रोमो को पहले ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना दिया है और अब इंतज़ार है पूरे एपिसोड का। प्रोमो में दिखाया गया है कि स्टंट शुरू होते ही जहां ओरी पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं चीते की मौजूदगी इस चुनौती को और भी खतरनाक और रोमांचक बना रही है। मज़ेदार बात यह है कि उनके चेहरे पर डर, घबराहट, हिम्मत और इस शो के लिए हां क्यों कहा? जैसे भाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं, जिससे यह प्रोमो, एक्शन के साथ-साथ मनोरंजन से भी भर गया है। ओरी का मजेदार अंदाज़ और इस हाई-ऑक्टेन स्टंट का कॉम्बिनेशन दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को रिलीज होगी

मुंबई/एजेन्सी

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आगामी फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। केवीएन प्रोडक्शंस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया। प्रोडक्शन हाउस द्वारा शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा था, 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में। 60 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन लेकर आ रहे हैं 'हैवान'। 'हैवान' एक दमदार थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। फिल्म में श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी।केवीएन प्रोडक्शन और थेस्पियन फिल्म्स प्रोडक्शन की फिल्म 'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है।इस बीच, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने हाल ही में फिल्म 'भूत बंगला' के लिए फिर से साथ काम किया है। इस फिल्म में परेश रावल, जिशु सेनगुप्ता, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी और असरानी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।'भूत बंगला' 2007 में रिलीज हुई 'भूल भुलैया' के बाद प्रियदर्शन की दूसरी हिंदी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और मनोज जोशी ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 2026 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन चुकी है।अक्षय कुमार की हालिया फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है। यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया है।

फिल्म में एक बड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, मीका सिंह, मुकेश तिवारी, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर और सयाजी शिंदे जैसे नाम शामिल हैं।इस बीच सैफ हाल ही में पुलकित की फिल्म 'कर्तव्य' में नजर आए। इसमें रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा और जाकिर हुसैन भी हैं। यह फिल्म एक पुलिस अफसर के बारे में है, जिसके परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। उसे यह तय करना है कि अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी नौकरी की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए वह किस हद तक जा सकता है।

सलमान खान को बांद्रा में छह मंजिला रिहायशी इमारत बनाने की मिली मंजूरी

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही बांद्रा में अपने परिवार के लिए समुद्र के किनारे छह मंजिला नया घर बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीजेडएमए) ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्लॉट एक्टर की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। यह नया घर बांद्रा के चिम्बाई इलाके में बनेगा, जो सलमान खान के मौजूदा घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट्स' से थोड़ी ही दूरी पर है। सलमान खान 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। गौरतलब है कि 2024 में, बाइक पर सवार दो हमलावरों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग की थी। जांच में पता चला कि हमलावर बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। इस घटना के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उन्हें वाई प्लास सुरक्षा दी गई। जिस बालकनी से वे अपने फैंस का अभिवादन करते थे, उसे बुलेटप्रूफ ग्लास से सुरक्षित कर दिया गया है। एमसीजेडएमए के सूत्रों के मुताबिक, नया घर सलमान खान की मां सलमा खान के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन पर बनाया जाएगा। इस प्लॉट पर पहले 1956 से पहले बना एक दो-मंजिला घर था, जिसे खरीदने के बाद परिवार ने उसकी जर्जर हालत के कारण गिरा दिया था। नई इमारत में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग और छह मंजिलें होंगी। इसका कुल कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 1,014 वर्ग मीटर होगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 'सच डेवलपर्स' द्वारा किया जाएगा। बीएमसी ने अक्टूबर 2025 में इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती परमिट (आईओडी) जारी किया था।

खबर है कि निर्माण के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसके बजाय, परिसर और आसपास के इलाके में स्थानीय प्रजातियों के नए पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्य सड़क से दूर एक शांत गली में स्थित यह नया घर सलमान खान और उनके परिवार को पहले से अधिक सुरक्षा और प्राइवेसी देगा। हालांकि, इस प्रोजेक्ट को लेकर सलमान खान या उनकी टीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाल ही में सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में वैध और अंतरिम निषेधाज्ञा की शीट पेश की है, जिसमें फिल्म के निर्माण, प्रचार और वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

'बेबी डू डाई डू' का गाना 'इश्क कमीना' हुआ रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म बेबी डू डाई डू के मेकर्स ने अपना नया गाना इश्क कमीना रिलीज कर दिया है, और अभिनेता रचित सिंह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक भावुक नोट साझा किया, जिसमें उन्होंने इस गाने का हिस्सा बनने को अपने लिए बेहद खास बताया, खासकर क्योंकि यह बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित ट्रैक से जुड़ा हुआ है। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए रचित ने लिखा, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब यह आइकॉनिक गाना हमारी फिल्म से जुड़ा, हम सभी छोटे बच्चों की तरह खुश और उत्साहित हो गए। शाह रुख सर और ऐश्वर्या मैम के साथ जुड़े इस गाने का हिस्सा बनना किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं खुद को सच में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त मानता हूं। हमेशा से उनका प्रशंसक रहा हूं। उनका यह दिल से लिखा संदेश इस बात को दर्शाता है कि भारतीय सिनेमा के दो बड़े सितारों से जुड़े गाने का हिस्सा बनना उनके लिए कितनी खुशी की बात है।

साथ ही, यह पोस्ट शाह रुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रति उनके सम्मान और प्रशंसा को भी खूबसूरती से दर्शाती है, जिससे इश्क कमीना की रिलीज उनके लिए और भी खास बन गई है। इश्क कमीना के रिलीज के साथ ही बेबी डू डाई डू अपनी 3 जुलाई 2026 की रिलीज से पहले दर्शकों के बीच उत्साह को और बढ़ा रही है।

आस्था

जल ही जीवन और आस्था है: असम के कामरूप जिले के गराल (खेलियापारा) में रविवार, 28 जून 2026 को पारंपरिक 'भेल पूजा' के दौरान जल देवताओं की आराधना करते ग्रामीण। इस खास 'भेलदिया जल पूजा' में लोग पानी के प्रति अपनी कृतज्ञता और आस्था प्रकट करते हैं।

मिड-डे शोबिज आइकन अवार्ड्स

शहर अभिनेता अभिमन्यु सिंह रविवार को मुंबई में आयोजित 'मिड-डे शोबिज आइकन अवार्ड्स 2026' के रेड कार्पेट पर अपने खास अंदाज़ में नज़र आए।

उज्ज्वल निकम ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'प्रहार' में राजकुमार राव के अभिनय की सराहना की

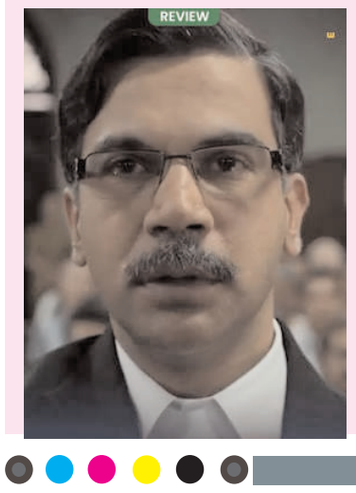

मुंबई/भाषा

प्रख्यात लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'प्रहार' में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता राजकुमार राव की सराहना की है। निकम ने कहा कि अभिनेता ने इस फिल्म में प्रामाणिकता और भावनात्मक गहराई ला दी है। यह फिल्म 'थ्री ऑफ अस' और 'पाताल लोक' के लिए मशहूर अविनाश अरुण के निर्देशन में बन रही है। 'प्रहार' 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद जिंदा पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ चले मुकदमे में उज्ज्वल निकम की भूमिका पर आधारित है। निकम ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, राजकुमार राव ने बेहतरीन अभिनय किया है और अविनाश अरुण का निर्देशन बेहद प्रभावशाली है। 'प्रहार' एक सरकारी वकील के रूप में केवल मेरे सफर को ही नहीं बल्कि एक पति और पिता के रूप में भी मेरे जीवन को प्रामाणिक रूप से दर्शाती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सभा सदस्य ने कहा, लोग फैसलों को याद रखते हैं, लेकिन उन फैसलों को लेने से पहले की रातों को बहुत कम लोग याद करते हैं। 'प्रहार' उनके जीवन के उस पहलू को दिखाती है, जो कभी सुर्खियों में नहीं आई।'' निकम ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों और 26/11 आतंकी हमलों समेत कई चर्चित मामलों में मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा, ''मैंने ऐसे मामलों में दलीलें रखीं, जिन्हें पूरा देश देख रहा था। उस जिम्मेदारी के साथ आने वाले अकेलेपन के बारे में मैंने कभी बात नहीं की। यह फिल्म उस पहलू को सामने लाती है। यह घटनाओं के प्रति ईमानदार रहती है और ऐसा करते हुए वह उस कहानी को दिखाती है, जिसे शब्दों में बयां करने में मुझे खुद कठिनाई हुई।'' फिल्म 'प्रहार' में वामिका गब्बी, सिकंदर खेर और जयदीप अहलावत भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म सात अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजान ने किया है।

'स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी और लक्ष्य है, सहयोग करें'

स्वच्छता आंदोलन परिवार ने आयोजित किया स्वच्छता अभियान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुब्बल्ली। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता आंदोलन परिवार द्वारा रविवार को केशवापुर स्थित गणेश मंदिर के समीप यूरेका कॉलोनी पार्क में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा हुब्बल्ली सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र-73 मंडल के सचिव विनोदकुमार पटवा ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने आसपास के सभी निवासियों से ऐसे स्वच्छता अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद उमा मुकुंद से पार्क में एक हाई मास्टलाइट लगाने का अनुरोध किया, ताकि पर्याप्त रोशनी रहने से असामाजिक गतिविधियों पर रोक लग सके और नागरिक सुरक्षित वातावरण में पार्क का उपयोग कर सकें। पार्षद उमा ने भी नागरिकों से पार्क की स्वच्छता बनाए रखने, कचरा न फैलाने तथा स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। इस स्वच्छता अभियान में वार्ड क्रमांक 44 के व संस्था के अनेक सदस्य उपस्थित थे तथा स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रदर्शन

राजनीतिक प्रक्रिया में उपेक्षा और खुद को अलग-थलग किए जाने के खिलाफ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सरकार से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।

एआई के दौर में भी एमबीए डिग्री पर नियोक्ताओं का भरोसा बरकरार : रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण बिजनेस स्कूलों से निकलने वाले स्नातकों की उपयोगिता कम होने की आशंकाओं के बावजूद दुनिया भर के नियोक्ताओं का एमबीए डिग्री पर भरोसा कायम है। 'ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल' (जीएमएसी) की एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

यह रिपोर्ट जीएमएसी के वार्षिक वैश्विक कॉर्पोरेट भर्ती सर्वेक्षण पर आधारित है। जीएमएसी 'ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट' आयोजित करने के साथ-साथ दुनिया के प्रमुख बिजनेस स्कूलों का एक शीर्ष संगठन भी है।

रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न उद्योगों में आधे से अधिक नियोक्ताओं ने इस बात से सहमति जताई या प्रबल सहमति व्यक्त की कि नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के दौर में बिजनेस मैनेजमेंट की स्नातक डिग्री पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

हालांकि, नियोक्ताओं ने एक ऐसे क्षेत्र को लेकर साझा चिंता भी जताई है, जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है। यह क्षेत्र है 'पेशेवर व्यवहार' (प्रोफेशनलिज्म)।

इस सर्वेक्षण में 39 देशों के 621 भर्ती अधिकारियों और नियुक्ति प्रबंधकों ने भाग लिया। इनमें से आधे से अधिक दुनिया की सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाली 'ग्लोबल फॉर्च्यून 500' कंपनियों से जुड़े थे।

सर्वेक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों ने एमबीए और वित्त, प्रबंधन तथा डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत बिजनेस मास्टर डिग्रियों को शामिल करने वाली 'ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन' (जीएमई) पर कम से कम कुछ हद तक भरोसा जताया।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''वर्ष 2025 में 99 प्रतिशत नियोक्ताओं ने यह भरोसा जताया था कि जीएमई उनके संगठनों में सफल होने के लिए स्नातकों को तैयार करने में सक्षम है। वर्ष 2026 में एक भी उत्तरदाता ऐसा नहीं था, जिसने इस पर बिल्कुल भी भरोसा न होने की बात कही हो। इससे पता चलता है कि उद्योग जगत आज भी जीएमई के महत्व को स्वीकार करता है।'' जब नियोक्ताओं से पूछा गया कि उन्हें जीएमई स्नातकों पर भरोसा क्यों है, तो अधिकांश ने कहा कि ये स्नातक जटिल वैश्विक कारोबारी माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''यह कारण सातवें स्थान से बढ़कर सबसे प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2026 में लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाताओं ने वैश्विक जटिलताओं के बीच सफलतापूर्वक काम करने की जीएमई स्नातकों की क्षमता की सराहना की। यह वृद्धि नियोक्ताओं के क्षेत्र या उद्योग की परवाह किए बिना देखी गई।''

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जटिल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, लेकिन संचार कौशल और रणनीतिक सोच जैसे बिजनेस स्कूलों में विकसित होने वाले कुछ प्रमुख कौशलों को लेकर नियोक्ताओं के भरोसे में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

इसमें कहा गया है कि ऐसे समय में जब एआई सामग्री तैयार कर सकता है, डेटा का विश्लेषण कर सकता है और नियमित कार्यों को स्वचालित बना सकता है, तब संचार क्षमता, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की योग्यता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे विशिष्ट मानवीय गुणों की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इनकी नकल करना कठिन है।

रिपोर्ट में कहा गया, ''बिजनेस स्कूलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल यह नहीं है कि उन्हें एआई से जुड़े कौशल सिखाने चाहिए, हालांकि इस क्षेत्र में कमी वास्तविक है और बढ़ रही है। बल्कि उन्हें ऐसे स्नातक तैयार करने होंगे, जो तकनीकी दक्षता और मानवीय निर्णय क्षमता के संगम पर आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें।'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आधे से अधिक नियोक्ताओं का मानना है कि दूरस्थ या 'हाइब्रिड' कार्य प्रणाली अपनाने वाले व्यवसायों में बिजनेस डिग्री से प्राप्त कौशल पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और औषधि उद्योगों में यह धारणा अधिक मजबूत है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का गर्मजोशी से स्वागत किया।

कटमनल्लूर में भागवत कथा की शुरुआत आज

कथावाचक राजनंदिनी पहुंची बेंगलूरु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय राजपूताना सेवा संगठन के तत्वावधान में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा की शुरुआत सोमवार से कटमनल्लूर स्थित अभय स्वामी मंदिर में होगी। इस आयोजन में कथा का श्रवण कराने के लिए अयोध्या धाम से देवी राजनंदिनी रविवार को बेंगलूरु पहुंचीं।संस्था के सदस्यों व श्रद्धालुओं ने रविवार को यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर कथावाचक राजनंदिनीजी का स्वागत किया। स्वागत के दौरान पूरा स्टेशन जय श्रीराम और धार्मिक जयघोषों से गूंज उठा।

संगठन के पदाधिकारियों ने सभी श्रद्धालुओं को कथा में शामिल होने का निवेदन किया है ।

लोभ का सबसे अचूक इलाज है संतोष : साध्वीश्री मंगलज्योति

बेंगलूरु/दक्षिण भारत । स्थानीय वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हनुमंतनगर के तत्वावधान में आयोजित प्रवचन सभा में रविवार को जैन स्थानक भवन में विराजित साध्वीश्री मंगलज्योतिजी ने कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों प्रमुख कषायो में से लोभ व लालच को सबसे भयंकर और गहरा माना जाता है। इसे सब पापों की जड़ कहा गया है। इच्छा आकाश के समान अनंत है। भगवान महावीर ने लोभ को पाप के बाप की संज्ञा से उपमित किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य कषाय क्रोध, अहंकार, छल केवल एक दो दोष पैदा करते हैं लेकिन लोभ व्यक्ति के अन्दर हिंसा, चोरी, झूठ और अपमान जैसे सभी बुरे कर्मों को जन्म देता है लोभ कभी शांत नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी सीमित आवश्यकताओं में संतुष्ट रहता है वही सच्चा सुखी है। ङ्कङ्कउन्होंने कहा कि लोभ का सबसे अचूक इलाज संतोष है। लोभ को संतोष से जीता जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार कचोलिया ने किया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय विजय संभव फाउंडेशन (वीएसएफ) ने इवन हॉस्पिटल्स और आलोका विजन फाउंडेशन के सहयोग से मिल्लर्स रोड स्थित हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया।

शिविर में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान चिकित्सकीय परामर्श, रक्तचाप एवं रक्त शर्करा की जांच, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) परीक्षण, नेत्र परीक्षण, आवश्यकता अनुसार ईसीजी जांच करवाई तथा पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) परमेश्वर एवं पुलिस निरीक्षक अश्वत्थ आर. ने भाग लिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि राजहंस ने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

संकट के हर दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां बनीं ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने जब-जब किसी बड़े संकट का सामना किया है हर बार देश की सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे 2015 की विनाशकारी बाढ़ हो, कोविड-19 महामारी हो या फिर वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का संकट उत्पन्न करने वाला पश्चिम एशिया का हालिया संघर्ष।

विश्लेषकों और उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि हर राष्ट्रीय आपातकाल ने इस बात को और मजबूत किया है कि सरकारें देश की ऊर्जा जीवनरेखा को नियंत्रित करने वाली इन कंपनियों पर से अपनी पकड़ ढीली करने में क्यों कतराती रही हैं।

दशकों से भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की अक्सर कम मुनाफे, ईंधन मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप और बड़े परिचालन के लिए आलोचना की जाती रही है। इन्हें दो बार निजीकरण के दायरे में भी लाया गया था। वर्ष 2002 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को बेचने की योजना ने गति पकड़ी, जिसे उच्चतम न्यायालय के एक फैसले ने रोक दिया। इसके बाद 2020 में फिर से यह प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन पर्याप्त बोलियां न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि जब 2015 में अभूतपूर्व बाढ़ ने चेन्नई को जलमग्न कर दिया था, तब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और एचपीसीएल ने वैकल्पिक मार्गों से ईंधन पहुंचाने, डूबे हुए डिपो को बहाल करने और आपातकालीन सेवाओं को आपूर्ति जारी रखने के लिए दिन-रात काम किया।

इसी तरह, कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद इन कंपनियों ने लगभग बिना किसी बाधा के काम किया।

एफटीएस युवा के स्वयंसेवकों ने पौधारोपण अभियान में भाग लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार बेंगलूरु विकास प्राधिकरण(बीडीए)द्वारा आयोजित ऐतिहासिक 15 लाख पौधारोपण अभियान में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी(एफटीएस) युवा के 160 स्वयंसेवकों एवं उनके परिवारजनों ने पौधारोपण किया। युवा कोषाध्यक्ष साकेत गर्ग ने बताया कि इस अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों की प्रेरणादायी भागीदारी देखने को मिली।

युवा सचिव विकास गुप्ता के नेतृत्व में संयोजक मितेश खण्डेलवाल सहित अनेक पदाधिकारियों ने तय स्थल पर पौधे लगाए।

यशवंतपुर तेरापंथ महिला मंडल ने आयोजित की 'बागबान' कार्यशाला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय तेरापंथ महिला मंडल यशवंतपुर द्वारा रविवार को साध्वीश्री पावनप्रभाजी के सान्निध्य में यशवंतपुर सभा भवन में 'बागबान' कार्यशाला का आयोजन किया गया। साध्वीश्री पावनप्रभाजी ने कहा कि वर्तमान समय में परिवार रूपी बाग को स्नेह, संस्कार एवं संवाद के माध्यम से सदैव हरा-भरा रखना आवश्यक है। बच्चों में बचपन से ही धर्म के संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए जिसका सशक्त माध्यम है ज्ञानशाला, जहां उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण हो सके। माता-पिता का आचरण ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम आदर्श बनता है। परिवार में बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त समय भी दें।

वही घर स्वर्ग के समान बनता है जहाँ प्रेम, नैतिकता, विनम्रता, परस्पर सम्मान एवं संस्कारों का वातावरण होता है। साध्वीश्री उन्नतयशा जी ने महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाया।

महिला मंडल की अध्यक्ष रेखा पितलिया ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सदस्याओं ने अपनी-अपनी जिज्ञासाओं का साध्वीश्री ने समाधान पाया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ज्ञापन मंत्री टीना पितलिया ने किया।

'अहम् स्वयं-आत्मचिंतन, कृतज्ञता और आत्मपहचान' विषयक सत्र आयोजित

जीतो साउथ लेडीज विंग ने किया आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) साउथ लेडीज़ विंग द्वारा सक्षम अभियान के अंतर्गत 'अहम स्वयं, दि यूमन बिनीथ दि नॉइज़' विषय पर एक सत्र का आयोजन किया जिसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी दैनिक जिम्मेदारियों और अनेक भूमिकाओं के बीच स्वयं से पुनः जुड़ने, आत्मचिंतन करने और अपने भीतर की वास्तविक पहचान को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना था। साउथ की चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने कहा, महिलाएं जीवन भर मां, पत्नी, बेटी, बहू, देखभालकर्ता और प्रोफेशनल जैसी अनेक भूमिकाएं निभाती हैं, लेकिन इस सफर में अक्सर स्वयं को भूल जाती हैं। स्वयं के लिए समय निकालना, अपने भीतर झांकना और अपनी भावनात्मक खुशहाली का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है।

केकेजी संयोजिका पिंकी जैन ने कहा कि जब हम स्वयं को समझते हैं, तभी वास्तविक विकास की शुरुआत होती है। ङ्कप्रशिक्षक साक्षी चौहान ने सत्र की शुरुआत एक रोचक आइस-ब्रेकर गतिविधि से की, जिसने महिलाओं को उनके अदृश्य मानसिक एवं भावनात्मक बोझ को पहचानने तथा स्वयं को प्राथमिकता देने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने जीवन में मौजूद रिश्तों, सहयोगी तंत्र, अनुभवों और व्यक्तिगत क्षमताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही, स्वीकार करना' और छोड़ देना' जैसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों पर भी चर्चा की गई।कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण महिलाओं को उनकी विभिन्न भूमिकाओं से परे स्वयं की पहचान से जोड़ना रहा। पूरे सत्र में प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। इस अवसर पर जे पॉइंट अपेक्स संयोजिका अंजलि जैन, निधि पालरेचा, कविता मुथा एवं समिति सदस्याएं उपस्थित थी।

एमडीएमके के कई वरिष्ठ नेता और जिला सचिव द्रमुक में शामिल

चेन्नई। मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) के 150 से अधिक पदाधिकारियों के रविवार को औपचारिक रूप से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) में शामिल होने से पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इन पदाधिकारियों में राज्य स्तर के नेता, जिला सचिव, अधिवक्ता और छात्र शामिल हैं। यह कदम पार्टी प्रमुख वाइको के नेतृत्व में एमडीएमके की आम परिषद द्वारा द्रमुक से अलग होने की घोषणा करने के एक दिन बाद उठाया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक द्रमुक मुख्यालय 'अन्ना अरिवालयम' में ये नेता द्रमुक अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**